

सूरजपुर में सड़क पर उतरे जेन अल्फा

सरकारी हॉस्टल में बड़इंतजामी दूर करने की मांग

सूरजपुर के भुनेश्वरपुर प्री मैट्रिक छात्रावास की छात्राओं ने भोजन और अन्य सुविधाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है।

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और हॉस्टल की समस्या को लेकर अब जेन अल्फा मुखर हो चले हैं। बीते दिनों दुर्ग के धमधा में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से जेन अल्फा का गुस्सा फूटा है। यहां के भुनेश्वरपुर में प्री मैट्रिक छात्रावास की छात्राओं ने मेस और हॉस्टल की समस्या को लेकर सड़क पर विरोध जताया है।

भारी संख्या में छात्राएं सड़क पर उतर कर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं ने छात्रावास में समय पर भोजन नहीं मिलने और मेस में उचित व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। हॉस्टल अधीक्षक पर समस्याओं को न सुलझाने के गंभीर आरोप लगाए।

छात्रावास में मिलने वाली सुविधाएं सही नहीं हैं। जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।भोजन की व्यवस्था ठीक



नहीं होने के कारण कई छात्राएं अपने पैसों से बाहर जाकर खाना खाने को मजबूर हैं- छात्रा हरकत में सूरजपुर जिला प्रशासन छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका की कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है।प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस अमला मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने की कोशिश की है। ट्राइबल विभाग के सहायक संचालक बिजेंद्र एक्का भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत कर

उनकी समस्याएं सुनीं। अधिकारी ने छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई और व्यवस्थाओं में सुधार का भरोसा दिया है।अधिकारी की समझाइस के बाद छात्राओं ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। अधिकारियों ने छात्रावास की समस्या को हल करने की बात कही है। दूसरी तरफ छात्राओं ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो फिर से आंदोलन किया जाएगा।

अतरिया में गौवंशों की मौत का मामला सरपंच ने वीडियो को बताया भ्रामक

कबीरधाम। पंडरिया विकासखंड के अतरिया गांव में बने गौशाला से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था इस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि गौशाला संचालक की लापरवाही के कारण भूख प्यास से गौवंशों की मौत हुई है। इस मामले पर पर्दा डालने के लिए मृत गौवंश को पास की फोक नदी में बहाया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले में जब मामले को लेकर सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होंने वीडियो और इसमें किए गए दावों को भ्रामक बताया।वीडियो में दिखाए जा रहे मृत गौवंश को नदी में बहाए जाने के दावे पर ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला के समीप नदी बहती है। आसपास के कुछ गांवों में मृत गौवंश को नदी में प्रवाहित करने की परंपरा होने की बात भी कही। जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी अनुदान का बंदरवाट हो रहा है वो बिब्लुकल ही नियाधार और गलत हैं। सरकारी अनुदान का एक रुपया भी हमें नहीं मिलता है।हम अपने मद पर सारी व्यवस्थाओं को करते



हैं।इसमें चरवाहा की 12 हजार रुपए में रखा गया है। भूसा और पानी की व्यवस्था भी हमें ही करनी होती है।इसलिए जो लोग कहें अत्यवस्था की बात कह रहे हैं वो निराधार हैं- नरेंद्र मल्ला, ग्रामीण वहीं गांव के सरपंच नरेश साहू ने इस भ्रामक जानकारी को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा है। ग्रामीणों ने कहा कि गौशाला में भूख-प्यास या देखरेख में लापरवाही के कारण गौवंश की मौत होने जैसी कोई घटना उनके संज्ञान में नहीं आई है। वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक गौशाला में गौवंश के लिए पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था है।उनकी देखरेख के लिए चरवाहे की भी व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में रखे गए गौवंश के रखरखाव में किसी प्रकार की गंभीर समस्या उनके सामने नहीं आई है।

116 किलो गांजा जब्त, 13 तस्कर गिरफ्तार

महासमुंद-कोंडागांव।

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के निर्देशों के तहत महासमुंद पुलिस और कोंडागांव पुलिस ने पांच अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है। दो नाबालिंग सहित 13 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। महासमुंद पुलिस ने 23 अगस्त को गांजा तस्करी के तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 60।920 किलो गांजा जब्त किया है। जब गांजे की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख 46 हजार रुपये है। पुलिस ने इन मामलों में कुल 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें नाबालिंग भी शामिल है। तीनों मामलों में गांजा तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन और मोबाइल फोन सहित कुल 28 लाख 22 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पहली कार्रवाई थाना सिंघोड़ा पुलिस ने एनएच- 53 पर ग्राम गनियागीपाली के पास की। मुखबिर से सूचना मिली थी कि काले रंग की यूनिफॉर्म मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति पिछू बैग में गांजा लेकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर



बाइक को रोका और तलाशी लेने पर 15।720 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 7 लाख 86 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने गांजे के अलावा दो मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित कुल 8 लाख 36 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की। इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के निवासी कलीम शेख (33) और राजेश धुनधरे (24) को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के सोनपुर जिले से अमरावती महाराष्ट्र ले जाने की बात बताई। इसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई तलाठीखोल स्थित एनएच- 53 पर वाहन चेकिंग के दौरान की। मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रे रंग की टोयटा कार को रोककर तलाशी ली गई। कार की डिब्की से 33.780 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 16 लाख 89 हजार रुपये बताई गई है। इसके साथ एक मोबाइल और कार समेत कुल 19 लाख 19 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की

कोंडागांव के कोनगुड़ में गारमेंट फैक्ट्री से बदली तस्वीर

कोंडागांव। जिले के सुदूरवर्ती ग्राम कोनगुड़ में गार्मेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया है। इस गारमेंट फैक्ट्री की खास बात है कि यहां स्थानीय महिलाओं, युवाओं के साथ साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार का अवसर मिल रहा है।

नीति आयोग से मिले करीब 5 करोड़ रुपये की राशि से गार्मेंट फैक्ट्री तैयार की गई है। रविवार को कांकेर सांसद भोजराज नाग, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन की टीम की मौजूदगी में फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया। फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ आत्मसमर्पित नक्सली कभी इसी इलाके में हथियार उठाकर नक्सली गतिविधियों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर रोजगार को अपना भविष्य बनाया है। नक्सली कर्मांडर रजनु कोरॉम और कुलसाय कावड़े ने बताया कि साल 2013 में उन्होंने नक्सल संगठन ज्वाइन किया। साल 2025 तक नक्सल संगठन से जुड़े रहे। बस्तर के सभी जिलों में सक्रिय रहे। कई नक्सली घटनाओं में भी शामिल रहे। साल 2025 में सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया था। अब अपने गांव में ही गारमेंट्स फैक्ट्री में सिलाई सीखने का मौका



मिल रहा है। सरेंडर नक्सलियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। सांसद भोजराज नाग ने कहा- गार्मेंट फैक्ट्री के संचालन से क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अपने ही गांव और क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिल रहा है। इससे महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी रोजगार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रोजगार के साधन विकसित कर लोगों को स्थायी रूप से विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा- जब मैं कोंडागांव में कलेक्टर के रूप में पदस्थ था, उस दौरान नीति आयोग की ओर से जिले को 10 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। उसी

समय इस गार्मेंट फैक्ट्री की नींव रखी गई थी और अब इसका विधिवत संचालन शुरू हो गया है। आने वाले समय में कोनगुड़ और आसपास के लोगों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। यह पहल सुदूर क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि गार्मेंट फैक्ट्री अंडर ट्रेनिंग है। कुछ दिनों बाद इसमें प्रोडेक्शन शुरू होगा। सरेंडर नक्सली पुरुषों को भी इस गारमेंट फैक्ट्री में ट्रेनिंग दी जा रही है।

महंगे हुए गणपति महंगाई के चलते मूर्तियों की कीमतों में इजाफा

कोरबा। हिंदू धर्म में गणपति महाराज को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की पूजा सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। अतः पूजा और शुभ कार्य के पहले गणपति महाराज की वंदना की जाती है। गणपति पूजा की शुरुआत 14 सितंबर गणेश चतुर्थी पर्व से होगी। कोरबा में हर साल धूमधाम के साथ गणपति पूजा का उत्सव मनाया जाता है। इस साल भी अलग-अलग पूजा समितियां पूजा की तैयारियों में जुट गई है।

महंगे हुए गणपति

बीते कई महीनों से मूर्तिकार भगवान गणपति की मूर्तियों के निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। मूर्तियों को आकार देने का काम तेजी से जारी है। गणेश उत्सव समितियों के द्वारा मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू कर दी है, इस वर्ष गणेशोत्सव समितियों और आम नागरिकों को लंबोदर की प्रतिमा खरीदने के लिए अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल, कच्चे माल की कीमतों में उछाल और बढ़ती लागत का सीधा असर इस बार गणेश प्रतिमाओं के निर्माण पर



पड़ रहा है। मूर्तिकारों के अनुसार, इस साल मिट्टी, रंग, विभिन्न सजावटी सामग्रियों और मजदूरी की लागत में खासी बढ़ोतरी हुई है। जिसके चलते गणेश मूर्तियों की कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।

15 से 20 फीसदी तक बढ़े दाम

शहर के सीतामणी को गणेश मूर्तियों के निर्माण का हब माना जाता है, यहां न सिर्फ लोकल बल्कि पश्चिम बंगाल से भी कारीगर भी आकर ठहरते हैं और गणपति जी की मूर्ति का निर्माण करते हैं। यहां ठहरे मूर्तिकार गणेश प्रतिमा के साथ ही आने वाले नवरात्रि और अन्य उत्सव के लिए भी वह मूर्तियों को आकार देने में लगे हुए हैं।

एडवांस बुकिंग और विशेष प्रतिमाओं का क्रेज

?त्योहार को लेकर लोगों में पहले से ही तैयारी शुरू हो चुकी हैं। शहर की कई प्रमुख गणेश उत्सव समितियां इस बार प्रतिमा का विशेष आकार, मनमोहक रूप और भव्य सजावट पत्र करने के लिए लगातार मूर्तिकारों से संपर्क कर रही हैं। ?मांग और लागत को देखते हुए मूर्तिकारों द्वारा बड़े आकार और विशेष रूप से सजाई जाने वाली आदमकद मूर्तियों की अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसके तहत कुछ विशेष और बड़ी मूर्तियों के लिए एक कोमत 30 प्रतिशत तक एडवांस लिया जा रहा है, ताकि बुकिंग सुरक्षित रहे।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

बहन पर किया कमेंट्स, तो दोस्तों ने मारा चाकू

दुर्ग। भिलाई में शराब पीने के दौरान अपने ही साथी की बहन पर कमेंट्स करना युवक को भारी पड़ गया। कमेंट्स करने के बाद उसके ही दो दोस्तों ने मिलकर उसपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पूरा मामला भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र का है। दरअसल, पुलिस ने बताया कि हिमांशु नेवारे अपने दोस्त योगेश्वर वर्मा उर्फ बिच्छू और मनीष लोनहारे उर्फ पीला के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान हिमांशु ने अपने दोनों दोस्तों को चखना लाने भेजा। दोनों दोस्त रात में उंडे समोसे लेकर वापस लौटे। समोसा उंडा होने की बात को लेकर हिमांशु ने मनीष और योगेश्वर से बहस शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर हिमांशु ने योगेश्वर की बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बात से योगेश्वर और मनीष नाराज हो गए। गुस्से में दोनों ने हिमांशु पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ने हिमांशु पर कई बार चाकू से वार किए।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें: कलेक्टर

अम्बिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित विकास योजनाओं, जनहितकारी कार्यक्रमों, निर्माण कार्यों और प्रशासनिक लॉबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करें। बैठक में अपार आईडी निर्माण एवं जाति प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति, जन्म प्रमाणपत्र निर्माण हेतु कार्यवाही की समीक्षा की गई। इस दौरान एनएचएम पदों पर भर्ती की प्रगति, मुआवजा प्रकरणों, नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति सहित अन्य की समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व बैठकों एवं निरीक्षणों में दिए निर्देशों पर प्रगति सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने अतिरिक्त धान संग्रहण केंद्रों हेतु भूमि चिन्हान के निर्देश एसडीएम अम्बिकापुर को दिए। इस दौरान जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि पर समीक्षा की गई।

विकास कार्यों में गुणवत्ता का रखा जाए विशेष ध्यान: कमिश्नर

जगदलपुर। बस्तर संभाग आयुक्त एवं वीबी-जी राम जी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आयुक्त-सह-संचालक ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में बस्तर संभाग के सभी जिलों में संचालित वीबी-जी राम जी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों की संभाग स्तरीय समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, मानव दिवस सृजन, अधोसंरचना निर्माण एवं लॉबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह ने कहा कि बस्तर संभाग शासन की विशेष प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, संभाग के सभी जिलों में विकास कार्यों में तेजी आई है। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ अधोसंरचना एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने पर जोर देते हुए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

दत्तेवाड़ा। एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना दत्तेवाड़ा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। जिसके तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना दत्तेवाड़ा के तहत ग्राम तोयलंका कोटवारपारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद है। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण तथा सहायिका हेतु 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिये आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी तथा आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। जिस वार्ड (इगरीय क्षेत्र) के आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, आवेदिका का उसी जगत्सव होना, वार्ड (नगरीय क्षेत्र) की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए इच्छुक स्थानीय सभी पात्र आवेदिकाएं दिनांक 21 अगस्त से 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

बलौदाबाजार एसपी गौरव राय की मैराथन क्राइम मीटिंग

बलौदाबाजार। जिले में कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए बलौदाबाजार एसपी गौरव राय ने लगातार मीटिंग का दौर शुरू कर दिया। रविवार को एसपी ने मैराथन क्राइम मीटिंग ली है। पूरे दिन चली इस समीक्षा बैठक में जिले के बलौदाबाजार, कसडोल और भाटापारा, तीनों पुलिस अनुभागों की अलग-अलग समीक्षा की गई। बैठक में 31 जुलाई 2026 की स्थिति में लॉबित अपराध, मार्ग, शिकायतों और बीएनएसएस के तहत लॉबित विवेचनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। एसपी ने थाना और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबे समय से लॉबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया है।

पुलिस अधीक्षक ने समीक्षा बैठक को तीन चरणों में आयोजित किया। सुबह 10 बजे बलौदाबाजार अनुभाग के थानों और चौकियों की समीक्षा की गई। इसके बाद



दोपहर 12 बजे कसडोल अनुभाग और दोपहर 2 बजे भाटापारा अनुभाग की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रत्येक थाना और चौकी में लॉबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई और अधिकारियों से प्रकरणों के लॉबित रहने का कारण पूछा गया। क्राइम मीटिंग में एसपी गौरव राय ने लॉबित अपराध, मार्ग और शिकायतों को लेकर थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निराकरण लंबे समय से लॉबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों

को निर्देशित किया कि विवेचना के दौरान सभी आवश्यक साक्ष्यों का वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से संकलन किया जाए, ताकि प्रकरण न्यायालय में मजबूत तरीके से प्रस्तुत हो सके। एसपी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आंकड़ों में पेंडेंसी कम करना पर्याप्त नहीं है। मामलों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी ड्रह्स की धारा 193(9) के तहत पूरक चालान और अग्रिम विवेचना से जुड़े लॉबित मामलों की भी समीक्षा की गई। विवेचकों को निर्देश दिए गए कि लॉबित विवेचना में आवश्यक साक्ष्यों को समय पर संकलित करें और नियमानुसार न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच की

जाए। अनावश्यक रूप से शिकायतों को लॉबित न रखा जाए और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मार्ग मामलों में भी मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच और साक्ष्य संकलन पर जोर दिया जाए- गौरव राय, एसपी, बलौदाबाजार क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण को लेकर भी पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। जिले में अवैध शराब के कारोबार और तस्करी, जुआ-सट्टा तथा अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाते के निर्देश दिए गए।

एसपी ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, बल्कि बेसिक पुलिसिंग की भी मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए नियमित गश्त, पैट्रोलिंग और संधिध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

113 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन गिरफ्तार

सूरजपुर। सूरजपुर से साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच में 21 राज्यों तक फैले साइबर अपराध के नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

दरअसल सूरजपुर थाने में म्यूल अकाउंट की लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी द्वाइय पानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन पोर्टल के जरिए मिली थी। जानकारी में सामने आया कि करीब 150 अलग अलग बैंक खातों से साइबर धोखाधड़ी की गई है और इन खातों में करीब 113 करोड़ 32 लाख रुपये से ज्यादा की रकम का लेन-देन हुआ है। जांच के



दौरान इस साइबर फॉंड से जुड़ी कुछ रकम सूरजपुर के एक म्यूल अकाउंट में भी पहुंचने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने इस खाते और इससे जुड़े लोगों की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक यह म्यूल अकाउंट छ ह चक्रधारी एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन नाम की एजुकेशन संस्था से जुड़ा हुआ था। जांच में सामने आया कि भारतीय स्टेट बैंक की सूरजपुर शाखा में संस्था के नाम से संचालित इस खाते को देवनारायण चक्रधारी और महेश

कुमार चक्रधारी से जोड़ा गया था। पुलिस जांच में इस खाते से जुड़े साइबर अपराध का दायरा सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई और संस्था से जुड़े आरोपी महेश कुमार चक्रधारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पहले ही साइबर फ्रॉड के एक मामले में जेल में नरुद्ध रह चुका है। हालांकि इस मामले में उसके खाते में अब तक कितनी रकम पहुंची और कितने खातों से उसका सीधा संबंध रहा है इसकी जांच अभी जारी है।पुलिस का कहना है कि आरोपी संस्था का सदस्य था और संस्था से जुड़े म्यूल अकाउंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर वित्त मंत्री ने किया सादर नमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मां भारती के वीर सपुत एवं महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राजगुरु जी ने

देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा।उन्होंने कहा कि राजगुरु जी ने भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। देश की आजादी के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देशसेवा की भावना जागृत करने वाला है। श्री ओपी चौधरी ने कहा कि राजगुरु जी का जीवन हमें राष्ट्रहित के सर्वोपरि रखते हुए साहस, त्याग और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

आस्था का उमड़ा सैलाब : राजधानी में

निकली विशाल कांवड़ यात्रा

धरसीवा। सावन के पावन माह में रायपुर



शिवमय नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का शिवालयों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष भावेश बघेल के नेतृत्व में रविवार को भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। सिलयारी के छाता तालाब से बोल बम के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में भक्त मुक्तेश्वर महादेव मंदिर चरोदा पहुंचे। 20 किमी की यात्रा में जगह-जगह कांवड़ियों पर जोरदार स्वागत किया गया। भावेश बघेल ने कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति और आस्था का प्रतीक है। कांवड़िये दूर दूर से नगे पैर पैदल चलकर बोल बम के जयकारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा के रूप में भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बारिश भी हुई, लेकिन भक्तों का जोश नहीं थमा। बोल बम के जयकारों के साथ महिलाएं, बुजुर्ग और युवा आगे बढ़ते गए। सिलयारी से लेकर रैता कपसदा तिवरैया धरसीवा चरोदा में जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा जैसे ही धरसीवा पहुंची तो ग्राम पंचायत सरपंच साहिल खान और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुर्गेश बर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने कांवड़ यात्रा की ढाढ़ बजों के साथ भव्य स्वागत किया। चरोदा स्थित प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने पर भी कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। भावेश बघेल ने प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना भोलेनाथ से की। साथ ही विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया।

पहली बार किसी संगीत कार्यक्रम में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों ने गाया गाना

रायपुर। नीरवंदन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा माथाराम सुरजन सभागार में संगीत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें रायपुर के अलावा बिलासपुर, मल्हार, कोरवा और

बलौदाबाजार से आए गायकों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आकर्षण रहा छत्तीसगढ़ के जसगीत गायक श्री दुकालु यादव की उपस्थिति जिन्होंने उपस्थित श्रोताओं की मांग पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त सम्भवतः पहली बार किसी संगीत कार्यक्रम के मंच पर एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों ने अपनी गायन प्रस्तुति दी। रायपुर निवासी कवि, साहित्यकार एवम समाजसेवी श्री छबिलाल सोनी जी अतिथि गायक के रूप में शामिल हुए साथ ही उनके पुत्र मुकेश सोनी एवम पोते अनिकेत सोनी ने भी अपनी प्रस्तुति दी। ग्रुप डायरेक्टर श्रीमती वंदना तिवारी एवं नीरज पांडे ने बताया कि यह उनके ग्रुप का सातवां आयोजन रहा जिसमें पूर्व आयोजन की तरह इस बार भी नए गायकों को उनकी प्रतिभा को सामने लाने अवसर दिया गया। ग्रुप का आगामी आयोजन 18 सितम्बर को माथाराम सुरजन सभागार में ही आयोजित किया जायेगा।

मैनी एनीकट निर्माण कार्य के लिए 71 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जशपुर जिले के विकासखण्ड-चासाबेल की मैनी एनीकट निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ 99 लाख 57 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के निर्माण से भू-जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एवं आवागमन के साथ ही 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं 200 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सहित कुल 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के महंत भासीदास संग्रहालय सभागृह में युवा साहित्यकार करुणा सागर पण्डा के उपन्यास ‘कोहरा’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं, बल्कि उसे सजग करने और सही दिशा दिखाने का भी सशक्त माध्यम है। ‘कोहरा’ जैसे उपन्यास सामाजिक विषयों को विमर्श के केंद्र में लाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने युवा साहित्यकार करुणा सागर पण्डा को उनके उपन्यास के प्रकाशन पर बधाई देते हुए कहा कि संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण विषय पर लेखन के लिए साहस की आवश्यकता होती है। रचनाकार जब समाज की समस्याओं और वास्तविकताओं को अपनी लेखनी का विषय बनाते हैं, तो साहित्य सामाजिक चेतना का माध्यम बनता है।मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की धरती ने देश को अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार दिए हैं। विनोद कुमार शुक्ल जैसे मूर्धन्य रचनाकार को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित

विधायक मोहम्मद आदिल के घर पहुंचे



रायपुर। ब्लू वाटर हादसे में मृत युवक मोहम्मद आदिल के मोदहापारा स्थित निवास पर आज रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुनरत्न मिश्रा पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सात्वना दी और इस दुख की घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त की। विधायक श्री मिश्रा ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढाँढस बंधाते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विधायक श्री मिश्रा ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अंतक के पिता मोहम्मद यूनस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान रायपुर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, रायपुर तहसीलदार श्री राममूर्ति दीवान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सावन सोमवार पर अमरकंटक पहुंचे डिप्टी सीएम

- विजय शर्मा ने पूजा करके मांगी प्रदेशवासियों की खुशहाली**

गौरेला पेंड्रा मरवाही। सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अमरकंटक में मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम ने मां नर्मदा के उद्गम स्थल के दर्शन के साथ प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित स्वयंभू ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

पूजा के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अमरकंटक की धार्मिक एवं

राजधानी/छत्तीसगढ़

हर घर में हो छोटी-सी लाइब्रेरी: मुख्यमंत्री साय



किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्तिबोध की सृजनभूमि रही है और पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जैसे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के रचनाकार इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और समकालीन विषयों को साहित्य के माध्यम से समाज के सामने ला रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सिनेमा और साहित्य ने समय-समय पर समाज के संवेदनशील विषयों को सामने लाने का काम किया है। उन्होंने 'द केरल स्टोरी' और 'द कश्मीर फाइल्स' का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन और मार्मिक विषयों को उठाने पर मतभेद और विरोध के स्वर भी सामने आते हैं, लेकिन रचनाकार का दायित्व है

कि वह अपनी दृष्टि और संवेदना के साथ समाज के सामने विषय रखे। उन्होंने 'कोहरा' के लेखक के साहसिक प्रयास की सराहना की।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अच्छी पुस्तकें अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपने घरों में छोटी-सी लाइब्रेरी बनाने और बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर की समृद्धि केवल उसकी भव्यता में नहीं, बल्कि वहां उपलब्ध पुस्तकों और अध्ययन की संस्कृति में भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें पीढ़ियों के बीच ज्ञान, संस्कार और अनुभव का सेतु बनती हैं। इसलिए हर परिवार को अपनी रुचि

श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिल रही उत्कृष्ट शिक्षा : साय

रायपुर। श्रमिक हमारे

विकास की मजबूत नींव हैं। अपने परिश्रम से वे सड़कें, भवन, पुल और विकास की अनेक संरचनाएं खड़ी करते हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का संकल्प भी साकार होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

श्रमिक परिवारों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी विकसित

छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का सपना होगा पूरा

समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख 45 हजार 841 श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को आज व्यवस्थित यूनिफॉर्म में, आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में संवाद करते और शिक्षा के साथ



खेल तथा अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इन बच्चों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि उचित अवसर और अच्छी शिक्षा मिले तो कोई भी परिस्थिति प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 100 बच्चों के साथ की गई थी। इस वर्ष इसका विस्तार करते हुए 200 बच्चों को योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा का

अवसर दिया गया है। प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित प्रतिभावान बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रंगटा पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना कभी श्रमिक परिवारों के लिए कठिन सपना हुआ करता

था, आज राज्य सरकार उस सपने को साकार कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना केवल

जेन-जी को भटकाने की कोशिश - स्वास्थ्य मंत्री

- नीट छात्रों के साथ एनएसयूआई करेगी प्रदर्शन**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नीट यूजी कार्डसलिग 2026 में डेमिसाइल और अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन करने वाली है। घड़ी चौक से एनएसयूआई कार्यकर्ता नीट छात्रों के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सरकारी आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करेंगे। इस प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली में बैठे कुछ आका साजिश कर जेन-जी युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में दिमागी नक्सलवाद भरा हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरकार मेडिकल एडमिशन को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पहली बार राजस्व विभाग की टीम भी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल रहेगी। इससे प्रमाण पत्रों का गहन सत्यापन किया जाएगा जो भी गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।



किसी भी तरह का लूपहोल नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी एडमिशन प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और घेराव की तैयारी की जा रही है। आखिर ये लोग युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? कुछ भ्रमित

लोग एडमिशन प्रक्रिया को विवादों में लाकर उसे जानबूझकर देर कराने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल प्रवेश में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान मूल निवासी प्रमाण-पत्र और कैटेगरी/संवर्ग प्रमाण-पत्र की भी जांच की जाएगी, जिससे सीट का लाभ सिर्फ पात्र अभ्यर्थी को ही मिले।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इतिहास में पहली बार प्रदेश में एक साथ पांच मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज और 10 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में 48 घंटे तक मानसून की एक्टिविटी रहेगी तेज

रायपुर। प्रदेश में एक हफ्ते से मानसून की एक्टिविटी तेज है। कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं पर मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया के साथ ही एक द्रोणिका भी बनी हुई है। जिसके प्रभाव से मौसम अगले 48 घंटे तक मानसून के एक्टिव रहने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों के लिए 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

रायपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद भी 1 जून से लेकर अब तक प्रदेश में सामान्य से 4ब बारिश कम दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से अब तक सामान्य से सबसे अधिक बारिश साराढ़-बिलाईगढ़ में 54% बारिश अधिक दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया आज की स्थिति में वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया गंगेटिक वेस्ट

बंगाल और इससे लगे हुए उत्तर ओडिशा के ऊपर स्थित है। 24 घंटे में यह झारखंड, उत्तर ओडिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही एक द्रोणिका जो है वेलमार्ट लो प्रेशर एरिया से होते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। एक शीयर जोन भी है जो 22 डिग्री नॉर्थ में मध्य स्तर तक स्थित है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान बढ़ा था लेकिन रविवार दोपहर से जो मानसून की एक्टिविटी शुरू हुई है उसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आ रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। लेकिन आने वाले तीन-चार दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बुधवार से उत्तर छत्तीसगढ़ में एक द्रो स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। जिसके लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

युवा शक्ति : विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी

प्रो. मनोज डोगरा

भारत को यदि युवा देश कहा जाता है तो इसके पीछे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवंत शक्ति है, जो देश की दिशा और दशा बदलने को क्षमता रखती है। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, रचनात्मकता, साहस और परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और रोजगार के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, तब युवाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के संदर्भ में, देश की यह जनसांख्यिकीय शक्ति भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। लेकिन केवल बड़ी संख्या में युवाओं का होना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के उचित अवसर उपलब्ध हों। आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला उद्यमी भी बन सकता है। स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि तकनीक, ऑनलाइन शिक्षा और नए व्यवसायों के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं पैदा हुई हैं। भारत के अनेक युवा अपनी प्रतिभा के बल पर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। ज़रूरत है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को भी इन अवसरों से जोड़ा जाए। हालांकि बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव, कौशल और रोजगार के बीच अंतर, नशे की समस्या, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग तथा मानसिक तनाव जैसी चुनौतियां युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। इन समस्याओं को केवल युवाओं की जिम्मेदारी मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। परिवार, शिक्षण संस्थानों, समाज और सरकार, सभी को मिलकर समाधान तलाशना होगा। नशे की समस्या युवाओं के भविष्य के लिए विशेष चिंता का विषय है। जिस उम्र में युवा अपने सपनों को आकार दे सकता है, उसी उम्र में यदि वह नशे की गिरफ्त में आ जाए तो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और पूरा भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए नशे के खिलाफ केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, युवाओं को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, कौशल विकास और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना भी आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे बदलाव ज़रूरी हैं, जिनसे युवाओं में ज़रूरत है कि ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को खेल-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता बढ़ाना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में पर्यटन, बागवानी, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, आई.टी. और स्थानीय उत्पादों के क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। युवा केवल चुनाव के समय मतदान करने तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक और लोका्तांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाएं। समाज में व्याप्त कुरीतियों, भ्रष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक असमानता जैसे विषयों पर युवाओं की सकारात्मक भागीदारी परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। युवाओं में डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की समझ विकसित करना समय की आवश्यकता है।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

और वे भी शब्दादि सभी विषयों की अनुकूलता किवा प्रतिकूलता से हमारी तरह ही सुख तथा दुःख का अनुभव करते हैं। श्रीमद्भागवतपुराण में भी यही बात डंके की चोट घोषित की गई है, यथा-
जातसस्तमःप्रायः, अन्तः
स्पर्शासं विशेषिणः ।

(श्रीमद्भागवत 3 । 10 । 16)

अर्थात्- वनस्पति आदि सभी उद्भिज्ज ऊपर की ओर बढ़ने वाले हैं, तमोगुण के श्राधिक्य से मूछितप्रायः हैं और अपने अन्दर स्पर्शादि विषयों का अनुभव करते वाले हैं। महाभारत में तो स्पष्ट ही विस्तारपूर्वक इस रहस्य को प्रकट किया गया है, यथा-

सुखदुःखयोश्च ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्।

जोवं पर्ययामि वृक्षाणामचैतन्यं न विवृते ।।

(महाभारत शान्तिपर्व 184 । 17)

अर्थात्- क्योंकि वृक्ष सुख और दुःख का

अनुभव करते हैं, तथा कटने पर विरूढ़ हो जाते हैं, इसलिये वृक्ष अवश्य ही जीवधारी हैं। अचेतन नहीं हैं।

सूर्य में काला धत्रा

आधुनिक ज्योतिषियों ने बहुत परिश्रम करने के बाद सूर्य के विषय में एक दो नई बातें जानी हैं। उनमें से काला धब्बा भी एक है। सन् 1862 के फरवरी महीने में एक योरूपियन ज्योतिषी ने रशिय विश्लेषक यन्त्र द्वारा इस धब्बे का पता लगाया है। अनुमान से इसका परिमाण 62 हजार मील लम्बा और 62 हजार मील चौड़ा बताया जाता है। परमाणु कुछ भी क्यों न हो इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो केवल यह बताना है कि वर्तमान साइन्डिस्ट जिस खोज को मौलिक एवं अभूतपूर्व समझ कर फूले नहीं समाते वह खोज पुराणग्रन्थों में सहस्त्रों वष पूर्व लिखी जा चुकी है।

क्रमशः ...



डॉ. श्रीगोपाल नारसन

प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविधालय का प्रकाश देश विदेश में पहुंचाने और विश्वविधालय के सेवा केन्द्रों का विस्तार दुनिया के 140 देशों में साढ़े आठ हजार की संख्या तक करने का श्रेय अगर परमात्मा के बाद किसी को जाता है तो वह ब्रह्माकुमारीज संस्था की।
आध्यात्म के रास्ते राजयोग के माध्यम से सीधे परमात्मा शिव का बोध कराने वाली इस संस्था ने दुनिया से विकारों को दूर करने तथा पावन पवित्र बनने का ऐसा अभियान चलाया कि संस्था में जो साधक संख्या 400 तक थी,वह आज लाखों में है। जिसके लिए दादी प्रकाशमणि का कुशल नेतृत्व ही सफलता का कारक रहा है। दादी प्रकाशमणि कही कुशल प्रशासक नजर

ज्ञान/मीमांसा

युवाओं के हाथ लगा सरकारों को झुकाने का मंतर!

अजय बोंकिल

दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के पीछे कौन था, कॉकरोच जनता पार्टी किसके इशारे पर काम कर रही है, उसका राजनीतिक लक्ष्य क्या है या फिर झारखंड का ‘जवाबी’ छात्र आंदोलन अपने मकसद में कितना कामयाब रहा, इन सवालों से इतर अहम बात यह है कि युवाओं ने जंतर मंतर से उपजे इस मंतर को गहराई से आत्मसात कर लिया है कि अब सरकारों को झुकाने का एक ही तरीका है, सहकों पर उतरो और वो भी बिना किसी भय अथवा सौदेबाजी की नीयत के।

ऐसे में खुद को ‘सख्त’ जताने वाली सरकारें भी भीतर से हिली हुई हैं तथा जेन जी और जेन अल्फा के इस तेवर के आगे बेबस दिख रही हैं। युवाओं के लिहाज से यह फार्मूला कारगर होता भी दिख रहा है, भले ही इसे ‘अराजकता’, गुंडागर्दी अथवा ‘प्रायोजित’ कहा जाए।

इसके जवाब में खड़े किए जा रहे आंदोलनों की कोशिशों में वो दम दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो इसका जवाबी नरेटिव तैयार कर सके। युवा अपने इन स्वतस्फूर्त आंदोलनों से राजनीतिक दलों एवं उनसे जुड़े संगठनों को दूर रख रहे हैं। अलबत्ता कुछ मामलों में विपक्षी पार्टियां खुलकर युवाओं के पक्ष में आ गई हैं।

मसलन दिल्ली में पैलेट गन मामले में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पांच घंटे चले धरने के बाद पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग मान लीजिए जाना भी नीट पेपर लीक के खिलाफ चले उस सीजेपी आंदोलन की सफलता की अगली कड़ी मानी जानी चाहिए, जिसमें अतंतः केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

जंतर मंतर पर जेन जी आंदोलन के दौरान खतरनाक पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की इजाजत तथा उससे घायल युवक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सरकार और पुलिस शुरू से कहती आ रही है कि आंदोलन के दौरान पैलेट गन चली ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि हमने तो नहीं चलाई। लेकिन राहुल गांधी ने उस युवक को पेश कर दिया, जिसे पैलेट गन के कई छंरें लगे हैं।

दिल्ली एम्स की रिपोर्ट में भी यह बात साबित हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी ने पैलेट गन नहीं चलाई तो युवक को उसके छंरें लगे कैसे? उधर जंतर मंतर आंदोलन के दौरान कारंबाई को लेकर पुलिस के हलफनामे से



असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जांच कमेटी बनाने की बात कही है। शुरू में पुलिस इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने से बचती रही। भाजपा ने भी राहुल पर यह कहकर हमला किया कि वो वंदे मातरम् से ध्यान हटाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे तो शाम को कथित ‘ऊपर के आदेश’ के बाद अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन यह काम तो पुलिस 14 अगस्त को भी कर सकती थी, जब पैलेट गन पीड़ित युवक साहिल थाने में रिपोर्ट कराने गया था।

अज्ञात का अर्थ यही है कि इसमे साफ तौर पर कोई भी आरोपी नहीं होता। जांच के बाद आरोपी तय होता है। अगर उसी वक एफआईआर हो जाती तो यह मामला संसद में हंगामे का कारण भी नहीं बनता। सरकार कह सकती थी कि चूँकि जांच जारी है कि पैलेट गन किसने चलाई, कैसे चलाई आदि।

उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिर राहुल गांधी को भी 21 अगस्त को मीडिया पर इतनी देर तक कवरेज नहीं मिलता, जैसा कि मिला। हालांकि शुक्रवार की घटना से यही संदेश गया कि अगर लोग सड़क पर उतरें तो सरकार के पास उनकी मांग मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।

मध्यप्रदेश की ही बात करें तो जंतर मंतर आंदोलन का साफ असर जेन जी- जेन अल्फा की सोच और तेवर पर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बीते 10 दिनों में राज्य में ऐसे 6 बड़े प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें बच्चे बेखौफ सड़कों पर उतरे और अपनी मांगें मनवा कर माने। प्रजासन को झुकाने पर विवश किया। जेन जी-जेन अल्फा के इस निर्भीक व्यवहार से प्रशासन भी हक्का बक्का है। क्योंकि ये बच्चे अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार उनके आगे नतमस्तक होती दिख रही है।

उदाहरण के लिए इंदौर में शासकीय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिव्यांग छात्रा से मेस फीस की जबरन ज्यादा वसूली, छिंदवाड़ा के दूरस्थ गांव बीच बहरी में शिक्षकों द्वारा नियत समय तक अध्यापन न करने, विदिशा जिले के सिरोंज में बस का किराया घटाने, भोपाल के डीएमएस स्कूल के केन्द्रीय विद्यालय में मर्जर पर रोक लगाने, धार जिले के निसरपुर में माता शबरी बौडिंग स्कूल की लड़कियां खराब खाने को लेकर आधी रात थाना घेरने जा पहुंचना शामिल है।

इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत होस्टल अधीक्षिका को निर्लंबित करना पड़ा। उधर उज्जैन में लड़कियों के स्कूल को सांदीपनि स्कूल के नाम पर 12 किमी दूर ले जाने का निर्णय पलटना जैसे मामले शामिल हैं। यही स्थिति हमे उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रही है और यह ट्रेंड तेज होता दीख रहा है।

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों और अभ्यर्थियों का 25 दिनों तक चला आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज्यादा चतुर सुजान निकले। उन्होंने शुरू से ‘संवेदनशीलता’ दिखाते हुए पहले आंदोलनकारियों को कई गुटों में बांटा। एक बार लाठियां भी चलवाईं। अंत में राज्य में 2014 से 2025 के बीच हुई सरकारी भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला यह कोर्ट में नहीं टिकेगा। हुआ भी वही।

जब पूर्व परीक्षाओं में चयनित और नियुक्तियां पा चुके दो हजार से अधिक कर्मचारी इसके खिलाफ अदालत पहुंचने तो हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक यह कहकर लगा दी कि परीक्षाओं को बैक डेट से रद्द कैसे किया जा सकता है। यह मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस बीच आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन समाप्त करते हुए कहा कि इसे फिलहाल ‘स्थगित’ किया जा रहा है।

अगर सोरेन सरकार ने दो माह में पूर्व की सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द नहीं किया तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व की 22 परीक्षाओं को रद्द करने तथा 6 नई परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग स्वीकार भले ही कर ली हो, लेकिन आंदोलनकारियों की मुख्य मांग कि सारी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए को ठुकरा

दिया। यानी सारी जांचें सीआईडी ही करेगी। जिस पर परीक्ष रूप से नियंत्रण राज्य सरकार का ही रहेगा।

झारखंड में इस आंदोलन को भाजपा खुलकर समर्थन दे रही है। लेकिन जिन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, उनमें 2014 से 2019 के बीच हुई भर्ती परीक्षाएं तो राज्य में भाजपा शासन काल की हैं, तब पार्टी ने एक गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर एक आत्मघाती राजनीतिक प्रयोग किया था।

उनके कार्यकाल में पांच साल में जेपीएससी, जेएसएससी और कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 33 हजार 184 सरकारी पदों पर भर्तियां की गई थीं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा समर्थित आंदोलनकारियों को भाजपा शासनकाल में हुई नियुक्तियों की निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं था?

दूसरे, पुरानी सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय दूरगामी होता। क्योंकि ऐसी मांग मानने के लिए दूसरे राज्यों और यहां तक कि केन्द्र सरकार पर भी दबाव बनाया जा सकता है। ऐसे में देश में नई अराजकता की स्थिति बन सकती है। क्योंकि सारी नियुक्तियां भ्रष्टाचार से ही हुई हैं, यह तो कोई भी नहीं कह सकता।

इस स्थिति में मरण उन लोगों का है, जो मेहनत से परीक्षाएं पास करके नौकरी पाएं हैं। अब कल को कोई सभी पुरानी यूपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग करने को लेकर सड़कों पर उतरे तो क्या सरकार उसे मानेगी अथवा मानना चाहिए? क्या बगैर किसी गहन जांच के ऐसी मांग मानना उचित है?

दूसरे, केवल कॉस्मेटिक तरीकों से बहला कर अपने पाले में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए इस युवा पीढ़ी के मनोविज्ञान, सोच और समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता और गहराई समझना होगा। उनसे उस शैली और भाषा में संवाद करना होगा, जिसे वो समझते और जिस पर भरोसा करते हैं।

विश्वबन्धुत्व दिवस



जब सन 1937 में उस समय के प्रसिद्ध हीरा व्यापारी एवं जाने माने सेठ दादा लेखराज को परमात्मा के सत्य स्वरूप व भावी नई दुनिया का अलौकिक साक्षात्कार हुआ और उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति बलर्ड रिन्यूवल

कॉस्ट का निर्माण कर नई दुनिया की स्थापना के लिए उसमें निहीत कर दी। वही मात्र 14 वर्ष की आयु में रमा देवी नामक बालिका ने दादा लेखराज के प्रति पुत्रिवत् समर्पण करके अलौकिक ईश्वरीय ज्ञान रूपी यज्ञ में आहुति डालने का काम किया जिससे उन्हें भी ज्योति स्वरूप शिव व नई सतयुगी दुनिया के साक्षात्कार हुए और वे रमा देवी से प्रकाशमणि बन गईं हर किसी का मधुर मुस्कान से स्वागत कर दिल जीत लेने वाली कर्मयोगिनी

भारत की चुनावी व्यवस्था की अमेरिकी तारीफ से उठे सवाल

कातिलाल मांडेठ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का भारत की चुनावी व्यवस्था और मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की सार्वजनिक सराहना करना केवल दो देशों की चुनावी प्रणालियों की तुलना भर नहीं है, बल्कि यह भारत की लोकातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता भी है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार, टैरिफ और अन्य मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं। ऐसे माहौल में ट्रम्प का भारत की वोटर आईडी व्यवस्था का उदाहरण देकर अमेरिका में भी चुनावी पहचान को अधिक सख्त बनाने की वकालत करना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया मंच पर भारत की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब भारत में मतदाताओं की पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था है तो अमेरिका में वैध फोटो आईडी के बिना मतदान की अनुमति क्यों होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी संसद से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ को पारित करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिकी चुनाव में केवल अमेरिकी नागरिकों को ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उनके इस बयान ने एक बार फिर अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में मतदाता पहचान और नागरिकता के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

भारत में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था कोई अचानक बनाई गई व्यवस्था नहीं है। देश में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो पहचान पत्र की शुरुआत कई चरणों में हुई और बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया। 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करने की दिशा में तेजी से काम किया। 1994 से देशभर में इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ईपीआईसी की व्यवस्था शुरू हुई और बाद में यह व्यवस्था देश के अधिकांश मतदाताओं तक पहुंची। डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ ई-ईपीआईसी की सुविधा भी शुरू की गई।

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में चुनाव कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। करोड़ों मतदाता, अलग-अलग भाषाएं, भौगोलिक परिस्थितियां और दूरदराज के क्षेत्रों में मतदान केंद्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना भारतीय चुनाव व्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी लोकातांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल करता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग लगातार मतदाता सूची, पहचान, मतदान केंद्र और चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा है।

भारत में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज है, हालांकि चुनाव आयोग की निर्धारित व्यवस्था के तहत अन्य स्वीकृत पहचान दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि मतदान करने वाला व्यक्ति वही है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। पहचान की यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यही वह पहलू है जिसकी ओर ट्रम्प ने अमेरिका के संदर्भ में ध्यान दिलाया है। अमेरिका में चुनाव व्यवस्था भारत से काफी अलग है। वहां चुनाव कराने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मतदाता पहचान से जुड़े नियम भी राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में फोटो पहचान पत्र की आवश्यकता अधिक सख्त है, जबकि कुछ राज्यों में पहचान के लिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। इसी अंतर को लेकर अमेरिका में वर्षों से राजनीतिक बहस चल रही है।

ट्रम्प जिस ‘सेव अमेरिका एक्ट’ की वकालत कर रहे हैं, उसका उद्देश्य अमेरिकी संघीय चुनावों में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को

सख्त करना है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देने और मतदान के समय फोटो पहचान पत्र दिखाने जैसी शर्तों को मजबूत करने की बात कही गई है। डाक मतपत्रों से जुड़े नियमों को भी अधिक कड़ा करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह अभी कानून नहीं बना है और इसे लेकर अमेरिकी राजनीति में गहरा मतभेद है।

रिपब्लिकन नेताओं और ट्रम्प समर्थकों का तर्क है कि चुनाव में मतदाता की पहचान और नागरिकता की जांच मजबूत होने से चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बढ़ेगा। उनका मानना है कि मतदान का अधिकार केवल पात्र नागरिकों तक सीमित रहना चाहिए और इसके लिए स्पष्ट पहचान व्यवस्था ज़रूरी है। दूसरी ओर डेमोक्रेट और इस कानून के विरोधी पक्ष का तर्क है कि अमेरिका में गैर-अमेरिकी नागरिकों का मतदान पहले से ही प्रतिबंधित है। उनका कहना है कि अत्यधिक दस्तावेजी शर्तें उन अमेरिकी नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, जिनके पास आसानी से उपलब्ध पहचान या नागरिकता संबंधी दस्तावेज नहीं हैं।

यहीं से भारत और अमेरिका की चुनावी व्यवस्था के बीच मूल अंतर भी सामने आता है। भारत में चुनाव आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था के रूप में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की निगरानी करता है, जबकि अमेरिका में चुनावी प्रशासन का बड़ा हिस्सा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए अमेरिका में एक समान राष्ट्रीय मतदाता पहचान व्यवस्था लागू करना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कठिन मुद्दा बना हुआ है। दुनिया के दूसरे लोकातांत्रिक देशों में भी मतदाता पहचान के अलग-अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन में कई चुनावों के लिए मतदान केंद्र पर फोटो पहचान पत्र दिखाने की व्यवस्था लागू की गई है,

जबकि कनाडा में पहचान और पते को प्रमाणित करने के लिए अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी मतदाता पहचान को लेकर भारत से अलग व्यवस्था है। इससे स्पष्ट होता है कि चुनावी पहचान का कोई एक वैश्विक मॉडल नहीं है। हर देश ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार प्रणाली विकसित की है।

ऐसे में ट्रम्प का भारत की चुनावी व्यवस्था को उदाहरण बनाना निश्चित रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव प्रक्रिया को लेकर समय-समय पर राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर मतदाता सूची और चुनाव आयोग की भूमिका तक विपक्षी दल कई मुद्दे उठाते रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना और संस्थाओं से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि राजनीतिक बहस तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित हो।

ट्रम्प के बयान ने भारत में इसी राजनीतिक बहस को एक नया संदर्भ दे दिया है। जिस समय भारत में कुछ राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय मतदाता पहचान व्यवस्था का उदाहरण देकर अपने देश में चुनाव सुधार की मांग कर रहा है। यह स्थिति निश्चित रूप से विचार करने योग्य है।

हालांकि भारत में चुनाव व्यवस्था की आलोचना करने वाले सभी सवालों को केवल ट्रम्प के बयान के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में चुनाव आयोग सहित सभी संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर चर्चा आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक दलों को यह भी समझना चाहिए कि किसी व्यवस्था की आलोचना और उसकी विश्वसनीयता पर बिना पर्याप्त प्रमाण के लगातार संदेह पैदा करना दो अलग बातें हैं।

आज का इतिहास

1351 सुल्तान फिरोजशाह तुगुलक़ तृतीय की ताजपोशी ।

1888 एक पाकिस्तानी गणितज्ञ, तर्कज्ञ, राजनीतिक सिद्धांतवादी, इस्लामी विद्वान और खाकसार आंदोलन के संस्थापक अल्लामा मशरिफी का निधन हुआ।

1916 टोलेन्बर्ग के युद्ध में रूस ने जर्मनी को पराजित किया।

1917 ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवान् दे रहे 7 भारतीयों को पहली बार क्रिि २स कमीशन मिला।

1926 पाँचवीं लोकसभा के सदस्य बाबूराव काले का जन्म हुआ था।
1940 लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया सोवियत संघ में शामिल हुए।

1952 भारतीय राज्य तमिलनाडु में सबसे पसंदीदा अभिनेता और राजनेताओं में से एक विजयकान्त का जन्म।

1957 भारतीय पोलो टीम ने विश्व कप जीता।

1963 सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के सोलह विरोधियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया।

1977 सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालय अभियान हल्लिया बंदरागाह से शुरू।

1980 ज़िम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।

1988 ईरान और इराक के बीच लंबे युद्ध के बाद सीधी बातचीत का दौरा शुरू।

1991 बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना।

1992 ब्रिटिश अखबार ने राजकुमारी डायना की बातचीत का ब्योरा जारी किया, जिसमें ऊ-२होंने प्रिंस से शादी पर नाखुशी जाहिर की थी।

1994–भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का जन्म।

1997 मासूमा इब्नेकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनीं।

2001 आस्ट्रेलिया के लोग स्पिनर शेनवानर्न ने टेस्ट क्रिकेट में 400 टेस्ट विकेट लिए।

2003 मुंबई में कार बम विस्फोट में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और 150 से अधिक घायल।

2008 मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008–09 के लिए सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को बीमा करने का अनुरोधन किया।

2011 श्रीलंका सरकार ने देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष बाद वापस लिया।

2012 चाँद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉंग का निधन।

2018 भारत के शॉटपुट एथलीट तेजेंदरपाल सिंह तूर ने जकार्ता ओलंपिक खेलों में रिकार्ड प्रदर्शन कर सोने का तमगा हासिल किया।

दिमागी नक्सली की बहस और लाल किले से निकले शब्दों की चुभन

सौरभ वार्णय

लोकतंत्र में शब्दों की अपनी शक्ति होती है। शब्द कभी भरोसा पैदा करते हैं, कभी चेतावनी देते हैं, कभी उम्मीद जगाते हैं और कभी राजनीतिक बहस को इतना तीखा बना देते हैं कि उनके अर्थ से अधिक उनके इस्तेमाल पर चर्चा होने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश की आंतरिक चुनौतियों, राष्ट्रविरोधी सोच, विकास और रा्यि एकता से जुड़े कई मुद्दे उठाए। इसी क्रम में यह उन्होंने दिमागी नक्सली जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह स्वाभाविक है कि उस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस हो। प्रश्न यह है कि आखिर दिमागी नक्सली से तात्पर्य क्या है और लाल किले जैसे सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच से निकला यह शब्द विरोधियों को क्यों चुभ रहा है?

सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दिमागी नक्सली कोई सामान्य कानूनी या संवैधानिक श्रेणी नहीं है। इसे मुख्यतः राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द माना जा सकता है। सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिन पर आरोप लगाया जाता है कि वे हिंसक नक्सली विचारधारा, राज्य-विरोधी सोच या लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास को वैचारिक स्तर पर बढ़ावा देते हैं, भले ही वे स्वयं हथियार उठाकर हिंसा में शामिल न हों लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। किसी व्यक्ति की सरकार से असहमति, किसी नीति का विरोध, किसी आंदोलन का समर्थन अथवा सत्ता की आलोचना को सीधे दिमागी नक्सलवाद कह

देना लोकतांत्रिक विमर्श के लिए उचित नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना देशद्रोह नहीं है और विपक्षी विचार रखना राष्ट्रविरोध नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति या संगठन वास्तव में हिंसा, अलगाववाद, संवैधानिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से गिराने या प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के समर्थन में सक्रिय है, तो उसकी विचारधारा पर गंभीर प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है।

यानी फर्क करना जरूरी है—असहमति और हिंसक विचारधारा में, आलोचना और राष्ट्रविरोध में, विपक्ष और उग्रवाद में। लाल किले की प्राचीर केवल भाषण देने का मंच नहीं है। यह भारत की स्वतंत्रता, संविधान, लोकतंत्र और करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसलिए वहां से प्रधानमंत्री के मुख से निकला प्रत्येक शब्द राजनीतिक बयान से कहीं अधिक महत्व रखता है। जनता उसके शब्दों में सरकार की दिशा और भविष्य की प्राथमिकताओं का संकेत खोजती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी तीखे या असामान्य शब्द पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो जाती हैं। विरोधियों को दिमागी नक्सली शब्द चुभने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के बीच पहले से ही अविश्वास की खाई गहरी है। जब सत्ता पक्ष किसी विचारधारा या समूह पर गंभीर आरोप लगाने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, तो विपक्ष को आशंका होती है कि कहीं असहमति की व्यापक श्रेणी को ही राष्ट्रविरोध के दायरे में तो नहीं लाया जा रहा। यही आशंका राजनीतिक विवाद को जन्म देती है। लेकिन इस बहस का



दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत ने दशकों तक नक्सल हिंसा की चुनौती झेली है। जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले, विकास कार्यों में बाधा और निर्दोष नागरिकों की मौत ने अनेक परिवारों को प्रभावित किया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए विकास, शिक्षा, रोजगार, प्रशासनिक पहुंच, न्याय और स्थानीय लोगों का विश्वास भी आवश्यक है।

यहीं दिमागी नक्सलवादजैसी अवधारणा पर गंभीर विमर्श की जरूरत पड़ती है। यदि किसी हिंसक विचारधारा का प्रभाव समाज में वैचारिक स्तर पर फैलता है, तो उसका मुकाबला लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से किया जाना चाहिए। लेकिन इस काम में सबसे बड़ा हथियार तर्क और संवाद होना चाहिए, लेबल नहीं। भारत की ताकत ही उसकी विविधता है। यहां वामपंथी विचार भी हैं, दक्षिणपंथी विचार भी हैं, समाजवादी विचार भी हैं, उदारवादी विचार भी हैं और अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक धाराएं भी हैं। इनमें से हर विचार से सहमत होना संभव नहीं, लेकिन हर असहमति को देशविरोधी बताना लोकतांत्रिक परंपरा को कमजोर कर सकता है। वास्तविक चुनौती यह है कि देश विरोधी हिंसक गतिविधियों और लोकतांत्रिक

असहमति के बीच स्पष्ट रेखा कैसे खींची जाए। यदि यह रेखा धुंधली होती है तो राजनीतिक शब्दावली समाज को बांट सकती है। यदि यह रेखा स्पष्ट रहती है तो सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों मजबूत होते हैं।

प्रधानमंत्री के भाषणों की एक विशेषता यह रही है कि वे अक्सर राजनीतिक संदेश के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय अभियान का आह्वान भी करते हैं। लाल किले से दिए गए भाषण का महत्व इसी कारण बढ़ जाता है। यह अक्सर केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने का नहीं, बल्कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों को व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से रखने का भी होता है इसलिए प्रधानमंत्री के किसी कथन को केवल राजनीतिक चरमे से देखने के बजाय उसके व्यापक संदर्भ को समझना चाहिए। यदि दिमागी नक्सली शब्द का उद्देश्य हिंसक विचारधारा के वैचारिक समर्थकों की ओर संकेत करना है, तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या है। कौन व्यक्ति या कौन-सी गतिविधि इस श्रेणी में आती है? क्या केवल सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आएगा? क्या किसी नीति का विरोध करने वाला नागरिक भी इसमें शामिल होगा? इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर लोकतांत्रिक समाज में बेहद जरूरी हैं। क्योंकि शब्द जिनावा बड़ा मंच पाता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है।

विपक्ष की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि सरकार किसी गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती

आर्थिक दबाव की रणनीति : ईरान ही नहीं, साथ देने वालों तक पहुंचेगी आंच

पवन

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसाइल की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के करीब छह महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने अभियान को अब जिस भाषा और स्वर में आगे बढ़ाया है, वह पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट को एक नए और अधिक व्यापक आर्थिक मोर्चे की ओर ले जाने का संकेत देता है। दरअसल, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर आर्थिक कार्रवाई करने का एलान किया है, जिसे उन्होंने इकनॉमिक डी-डे नाम दिया है।

इसके तहत ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है, जो किसी भी रूप में ईरान के साथ सहयोग कर रहे हैं। साफ है कि अमेरिका अब केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि दुनिया के दूसरे देश भी तेहरान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों पर पुनर्विचार करें। ट्रंप की रणनीति ईरान के इर्द-गिर्द पनपी अवैध तेल-अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने पर केंद्रित है, जिसमें ईरानी तेल की तस्करी और तीसरे देशों के जरिये ठेक के अवैध हस्तांतरण से जुड़े नेटवर्कों की कमर तोड़ना शामिल है।

जाहिर है कि इससे ईरान के तेल कारोबार और उसके वित्तीय लेनदेन पर असर पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ईरान पहले भी वर्षों तक अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। इसके बावजूद, उसने अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशें हैं। चीन, रूस व कुछ अन्य देशों के साथ उसके संबंध उदाहरण हैं कि व्यापक प्रतिबंधों के बाद भी किसी देश को पूरी तरह से



वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से काट देना आसान नहीं है।

ट्रंप प्रशासन की चुनौती यहीं से शुरू होती है। अगर अमेरिका अब उन देशों की भी निशाना बनाता है, जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो यह टकराव केवल अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा। तेल बाजार में किसी भी बड़ी अस्थिरता का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय गतिविधियों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लेकिन पश्चिम एशियाई संकट का स्थायी समाधान केवल आर्थिक घेराबंदी से संभव नहीं है। दबाव का उद्देश्य यदि बातचीत की मेज तक पहुंचना है, तो वह समझ में आता है, पर यदि दबाव ही अंतिम नीति बन जाए, तो उसके परिणाम अप्रत्याशित भी हो सकते हैं। पश्चिम एशिया पहले ही युद्ध व अस्थिरता से जूझ रहा है; ऐसे में एक व्यापक आर्थिक टकराव स्थिति की ओर जटिल ही करेगा।

पंजाब में बदलता सियासी समीकरण : अकेले चुनावी मैदान में भाजपा

कातिलाल मांडोत

पंजाब की राजनीति विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले ही नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को गर्म कर दिया है, लेकिन फिलहाल भाजपा की पंजाब इकाई अपने दम पर चुनाव लड़ने के पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़ी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के स्तर से सभाी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही जा चुकी है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या भाजपा वास्तव में अकेले मैदान में उतरेगी या सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने की स्थिति में पुराने सहयोगी अकाली दल के साथ फिर खड़ी होगी।

भाजपा और अकाली दल के बीच नजदीकी की चर्चा अचानक नहीं शुरू हुई। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद इन अटकलों की ओर बल मिला। इसके बाद अकाली दल का केंद्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों के समर्थन में आना भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा गया। दोनों दल लंबे समय तक पंजाब में साथ रहे हैं। वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह गठबंधन टूट गया था, लेकिन अब 2027 के चुनाव को देखते हुए दोनों पक्षों के बीच संभावित पुनर्मिलन की चर्चा फिर तेज है।

लेकिन गठबंधन की राह में सबसे बड़ी बाधा सीटों का बंटवारा है। अकाली दल पुराने फार्मूले को आधार बनाा चाहता है, जबकि भाजपा अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सीटों पर अपना दावा देख रही है। भाजपा का संगठन पंजाब में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और पार्टी का मानना है कि अब उसे सहयोगी की छोटी भूमिका में सीमित करना उसके राजनीतिक विस्तार के खिलाफ होगा। यही कारण है कि प्रदेश इकाई लगातार 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का संदेश दे रही है। भाजपा के लिए यह केवल चुनाव लड़ने का सवाल नहीं, बल्कि पंजाब में अपने



स्वतंत्र राजनीतिक आधार को स्थापित करने की कोशिश भी है।

पंजाब में भाजपा और अकाली दल के सामाजिक आधार भी अलग-अलग क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं। भाजपा का प्रभाव मुख्य रूप से शहरी और व्यापारिक वर्गों में माना जाता है, जबकि अकाली दल की पारंपरिक पकड़ ग्रामीण पंजाब और सिख मतदाताओं के एक हिस्से में रही है। दोनों का गठजोड़ होने पर यह सामाजिक और भौगोलिक समीकरण एक-दूसरे का पूरक बन सकता है। दूसरी ओर, भाजपा का मानना है कि अकेले चुनाव लड़ने से उसे अपने संगठन और विस्तार की वास्तविक ताकत का आकलन करने का अवसर मिलेगा।

इस राजनीतिक खींचतान के बीच सबसे बड़ा सवाल भगवंत मान सरकार के प्रदर्शन का है। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के लंबे शासन से नाराज मतदाताओं को बदलाव का सपना दिखाकर भारी बहुमत हासिल किया था। अब सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में है और चुनावी मुकाबला धीरे-धीरे सरकार के कामकाज के मूल्यांकन की तरफ बढ़ रहा है।

कानून-व्यवस्था पंजाब में सरकार के सामने सबसे गंभीर राजनीतिक चुनौतियों में से एक बनी हुई है। गैंग हिंसा, लश्कित हत्याओं और अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जनवरी 2026 में कानून-व्यवस्था को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच पुलिस के शीर्ष स्तर पर बदलाव की चर्चा भी सामने आई

थी। फरवरी में एक के बाद एक स्थानीय नेताओं की हत्या ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया। जुलाई में भी पुलिस की कमी और कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए।

नशे का मुद्दा भी पंजाब की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। सरकार ने युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगस्त में दावा किया कि अभियान के 500 दिनों में 70 हजार से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि सीमा पार से होने वाली तस्करी रोकने, पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके बावजूद विपक्ष का तर्क है कि केवल गिरफ्तारियों के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं; चुनावी राजनीति में असली सवाल यह होगा कि आम परिवारों को नशे की समस्या से वास्तविक राहत कितनी मिली।

पंजाब में अलगाववाद और खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों की चिंता भी सुरक्षा और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनी हुई है। सीमा से लगे राज्य के रूप में पंजाब के सामने नशा तस्करी, हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध और सीमा पार नेटवर्क जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही है कि कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को मजबूत रखा जाए और अलगाववादी विचारों को राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता का आधार न बनने दिया जाए। इसे किसी पूरे समुदाय से जोड़कर देखने के बजाय सुरक्षा और कानून के दायरे में देखना अधिक उचित होगा।

विकास के मोर्चे पर तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। भगवंत मान सरकार ने सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कामों और परियोजनाओं का दावा किया है। मार्च में सरकार ने करीब 497 किलोमीटर लंबी 237 ग्रामीण संपर्क सड़कों के नवीनीकरण की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। होशियारपुर में स्वास्थ्य और सड़क ढांचे से जुड़े 516 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा हुई।

राजनीति की बदलती भाषा

सुधीश पचौरी

उन्होंने कहा कि अब दिमागी नक्सल बचे हैं...ये मैकाले और मार्क्स की संतानें हैं...ये अफवाह फैलाते हैं...इनसे सावधान रहना है...। इतना कहना था कि अगले दिन एक सीनियर ‘दिमागी नक्सल जी’ भी ताल ठोकने लगे कि ‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है...।’ यह सीनियर जी का ‘कांक्रोच क्षण’ था, जो अचानक ‘दिमागी नक्सल क्षण’ में बदल गया था। हाय! जिन पर कभी नक्सलों को निपटाने की जिम्मेदारी थी, वही आज कह रहे हैं कि उन्हें अपने ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है! एक चर्चक कहिन: इसे कहते हैं कि ‘बिंबी थैले से बाहर...।’ एक सीनियर के दिमागी नक्सल होने के गर्व को देख कुछ और नामी ‘दिमागी नक्सल’ नजर आने लगे और कहने लगे: मैं भी ‘दिमागी नक्सल’...मैं भी ‘दिमागी नक्सल’...मैं भी ‘दिमागी नक्सल’...। ये ‘रोल रिवर्सल’ के दिन हैं। ‘नकारात्मक’ ही ‘सकारात्मक’ हुआ जा रहा है। ये राजनीति के प्रस्तावों व प्रस्थापनाओं के बदलने के दिन हैं। ये ‘शर्म’ के ही ‘बेशर्म’ हो जाने के दिन हैं।

एक बड़े ‘मी लॉर्ड’ जी ने किसी और संदर्भ में किसी को ‘कांक्रोच’ कह दिया, तो जबाब में तुरत एक पूरी ‘कांक्रोच जनता पार्टी’ ही बन गई और दिल्ली के ‘जंतर-मंतर’ पर आ बैठी और फिर उनके दबाव में एक दिन ‘न झुकने’ का दावा करने वाली सरकार भी झुक गई। ‘कांक्रोच पार्टी’ की मांगें मानी गईं। मंत्री जी को जाना पड़ा और अब भी सत्ता को जब-तब धमकी मिलती रहती है कि जरूरत पड़ी, तो हम फिर ‘जंतर-मंतर’ पर बैठ जाएंगे...और फिर सब हिलने लगते हैं। वे सातवें दशक के दिन थे। तब के सत्ताधारी दल के नेता ने विपक्ष के एक नेता को कह दिया कि वह ‘सीआईए’ का एजेंट है...तो अगले दिन वही नेता अपने गले में एक तख्ती लटका कर ले आए, जिस पर लिखा था, ‘हां, मैं सीआईए एजेंट

हैं या राजनीतिक खेमों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री का पद दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षा रखता है। उसी प्रकार विपक्ष की भूमिका भी केवल विरोध करने की नहीं, बल्कि वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करने की है।आज भारत को ऐसे राजनीतिक विमर्श की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रहित और लोकतांत्रिक असहमति एक-दूसरे के विरोधी न माने जाएं। देश की सुरक्षा भी जरूरी है और नागरिक स्वतंत्रता भी। विकास भी जरूरी है और सामाजिक न्याय भी। सरकार की मजबूती भी आवश्यक है और विपक्ष की प्रभावी आवाज भी।दिमागी नक्सली शब्द पर बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण वह प्रश्न है जिसे यह बहस सामने लाती है— क्या हम विचारों वास्ता केवल मुकाबला करेंगे या विचार रखने वाले व्यक्ति को ही दुरमन घोषित कर देंगे? भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का उतर स्पष्ट होना चाहिए। हिंसा का विरोध हो, आतंक और उग्रवाद के खिलाफ कठोरता हो, लेकिन विचारों का मुकाबला विचारों से हो। असहमति का जवाब तर्क से हो और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का जवाब कानून से।

लाल किले की प्राचीर से निकला हर शब्द इतिहास में दर्ज होता है। इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष—सभी की शब्दों की ताकत और जिम्मेदारी दोनों समझनी होंगी। राष्ट्रवाद को मजबूत करने का सबसे प्रभावी रास्ता केवल विरोधियों को नाम देना नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जिसमें असहमति के बावजूद नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और राष्ट्र की मुख्यधारा का हिस्सा महसूस करें। यही लोकतंत्र की असली शक्ति है और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान भी।



यदि आप घर को रिनोवेट करवाने की सोच रहे हैं, तो कुछ नया ट्राय कर सकते हैं। इन दिनों होम डेकोर के न्यू ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जो न सिर्फ इंटीरियर को खास बनाते हैं, बल्कि घर को न्यू लुक भी देते हैं। खासकर वॉल डेकोरेशन में काफी नए ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। इन्हें पहले से ज्यादा आर्टिस्टिक बनाया जा रहा है। साथ ही इको फ्रेंडली इंटीरियर से भी जोड़ा जा रहा है।

स्टोन आर्ट वर्क

दीवारों पर स्टोन का आर्ट वर्क भी काफी पसंद किया जा रहा है। इन्हें टीवी वॉल या फिर सेंटर वॉल पर ट्राई किया जा सकता है। दूसरी ओर, मार्केट में डिफरेंट तरह के स्टोन देखे जा रहे हैं, जो दीवारों के लिए काफी पसंद किए जाते हैं, इनमें कलर फुल स्टोन काफी डिफरेंट एंड ट्रेंडी लुक देते हैं।

वर्टिकल गार्डन

वर्टिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट काफी पसंद किया जा रहा है। बाहर के साथ-साथ इस तरह के गार्डन को घर के अंदर भी लगाया जा सकता है। ड्राईंग रूम के अलावा वॉशरूम में भी वर्टिकल गार्डन काफी अच्छे लगते हैं। वॉशरूम की वॉल पर यह गार्डन फ्रेशनेस का अहसास देंगे। वॉशरूम में मॉस वॉल भी लगवाई जा सकती है।

डिफरेंट म्यूरल्स

दीवारों पर म्यूरल्स लगवाना काफी कॉमन है। इसमें भी अब डिफरेंट वैराइटीज नजर आ रही हैं, जिनमें डिजिटल और उड़ी भी शामिल हैं। डिजाइनर्स की मानें तो वॉल से लेकर फ्लोर तक अट्रैक्टिव पेपर एंड म्यूरल्स देखे जा रहे हैं। वॉल पर कॉज्मिक और सी लाइफ़ काफी पसंद की जा रही है, इसके तहत दीवार पर नैचुरल कलर्स उभरते हैं।

खतरनाक है घर का सामान...



हर इंसान का इस दुनिया में एक छोटा सा आशियाना बनाने का एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है। अपनी सुख सुविधाओं की तमाम चीजों को वो इस घर में जुटाता है लेकिन तब क्या हो जब जरूरतों का सामान ही उसकी सहेत के लिए भारी पड़ जाए? हाल ही में हुए रिसर्च से यह बात सामने आई है कि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलु उपकरण जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रानिक उत्पाद जैसे टीवी और कम्प्यूटर, घरों में लगे परदे, एयर फ्रेशनर और यहां तक कि साबुन भी कई तरह की बीमारियों को न्यौता दे सकते हैं। जार्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मिल्टन इस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने रिसर्च में बताया कि फर्नीचर,टीवी, कम्प्यूटर, परदे, एयर फ्रेशनर और साबुन में भारी मात्रा में कैमिकल जैसे पैथलेट्स, फिनािल, फ्लोरीन युक्त रसायन मिले होते हैं। ये रसायन धूल के कणों में मिलकर हवा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। कई बार मां और बच्चे के शरीर में इन सामानों की वजह से कई सारे कैमिकल चले जाते हैं जिसका शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टीसीडीपी नामक कैमिकल जो कि गढ़ों में पाया जाता है के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। यह कैमिकल बच्चों के खेलते वक़्त उनके हाथों से मूह तक पहुंच जाता है जिससे बच्चों की सहेत बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। विश्व के कई इलाकों में इस कैमिकल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इयूक यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप टीम ने एक नई प्रसंग प्रकाशित की है जिसमें कैमिकल्स के वर्तमान इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। रटडी में पाया गया कि बच्चों के हाथ में अपशिष्ट कणों के रह जाने के कारण उन्हें कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। कुछ भी खाने से पहले बच्चों के हाथ जरुर धुलवाना। संभव हो तो बच्चों के हाथ ऐसे साबुन से धुलवाएं जो खुशबू से रहित हैं क्योंकि उनमें कैमिकल नहीं होते। कैमिकल वाले साबुन से हाथ धोना भी बीमारी को दावत देना है।

हमें टर्मरिक पिल्स की जरूरत नहीं...



आज कल पूरे विश्व में लोग हल्दी से मिलने वाले फायदों को पाने के लिए टर्मरिक पिल्स का सेवन कर रहे हैं। हल्दी से मिलने वाले फायदों से हम सभी भलीभांति परिचित है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज कल बाजार में हल्दी की गोलियां भी मिलती हैं। ये दवाइयां आज कल पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसे टर्मरिक साल्सीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय बाजार में भी हल्दी की ये गोलियां उपलब्ध हैं और आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे कर्कुमिन साल्सीमेंट के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारतीय लोगों को आयरन या कैल्शियम साल्सीमेंट की तरह इस हल्दी साल्सीमेंट को लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि अधिकतर भारतीय व्यंजनों में हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपको जरुरी हल्दी की मात्रा आसानी से मिल जाती है। हल्दी में कर्कुमिन नामक योगिक पाया जाता है जिसकी एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी क्षमताओं का कारण ही हल्दी इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक दिन में हल्दी की कितनी मात्रा उपयोग में लानी चाहिए तो यह बताना थोड़ा मुश्किल है। चूँकि हल्दी की तासीर गर्म होती है इसलिए यह अलग अलग लोगो पर निर्भर करता है की उसके उसे कितनी हल्दी खानी चाहिए। आमतौर पर डिशेज में एक या दो चम्मच हल्दी मिलाना उपयुक्त माना जाता है और इतने से ही आपको इससे मिलने वाले सारे फायदे मिल जाते हैं। पूरे उत्तर भारत में खाने में हल्दी का उपयोग किया जाता है खासतौर पर पंजाब और राजस्थान की अधिकतर कई मशहूर डिशेज में इसका भरपूर उपयोग होता है।



भले ही चीनी व्यंजन दुनिया भर में लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन भारतीय खाने से इसे टक्कर मिल रही है। भारतीय व्यंजन भी लोगों की थालियों में विश्वभर में जगह बना रहे हैं। विश्व के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। विश्व भर में चीनी भोजन स्थानीय खाने के बाद दूसरे स्थान पर है लेकिन भारतीय व्यंजन काफी लोकप्रिय हो चुके हैं और यह चीन को पीछे छोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में ही खाना बनाने के शौकीन लोग बहुत प्यार और धैर्य से खाना पकाते हैं। खाना बनाने की तकनीक ज्यादातर देशों में लगभग एक जैसी है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के व्यंजनों की बात करें तो हर जगह का खाना वहां के लोगों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। उत्तर भारत के लोग जहां खाने में मक्खन, स्थानीय मसाले, मीठ और चिकन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, वहीं दक्षिण में नारियल, करी पता, कई तरह के मिर्च और मसाले का प्रयोग ज्यादा होता है।

सैलानियों की पसंद

विदेशी सैलानियों के पसंदीदा व्यंजनों में भारतीय व्यंजन शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियावासी, अंग्रेज, डच और न्यू जिलैंड के पर्यटक भारतीय व्यंजनों का छक कर लुत्फ उठाते हैं। फ्रांसीसी लोग चीन, जापान, स्पेन और यहां तक की यूनान के व्यंजनों के मुकाबले भारतीय व्यंजन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यहीं बात ऑस्ट्रेलिया के लोगों के संबंध में भी देखी जा रही है। ऑस्ट्रेलियावासियों ने भारतीय व्यंजनों को दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में रखा है।

निफ्टम की पहल

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट निफ्टम ने देशभर से ऐसे 15 उत्पाद चिन्हित किए हैं, जो पीजा और बर्गर की तरह विश्व के बाजार में भारतीय व्यंजन के रूप में उतारे जाएंगे। इनमें हरियाणा का घेवर और बिहार का लिट्टी चौखा भी शामिल है। विदेशों में भारत के पारंपरिक भोजन की बढ़ती मांग के चलते निफ्ट भविष्य में भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्य बाजार के रूप में स्थापित होने जा रहा है। इसी को देखते हुए हरियाणा के घेवर और बिहार के लिट्टी चौखा जैसे उत्पादों को विश्व स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है।

ये व्यंजन होंगे शामिल

निफ्टम जिन भारतीय पारंपरिक खाद्यों को विश्व स्तर पर लॉंच करने की तैयारी में है, उनमें कश्मीर का गुस्तावा, पंजाब की चिकन करी, गुजरात का खाकरा, दक्षिण भारत का बैंबू स्टीम फिश, साउथ का वड़ा, बिहार का खाना, उत्तर भारत का अनारसा, कवाब, बिहार का लिट्टी चौखा, गुजरात का खांडवी, महाराष्ट्र की पूरन पोली, हरियाणा का घेवर, सत्तु और चावल का मुसुरा है। निफ्टम ने देश के 18 राज्यों में 39 गांव गोद लिए हैं।



वजन बढ़ाने के लिए करें

इस प्रकार का भोजन

विविध



चीनी नहीं अब इंडियन फूड...

रूस में भारतीय व्यंजन

रूस के मास्को में करीब 10 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां उत्तर भारतीय से लेकर दक्षिण भारतीय व्यंजन तक परोसे जाते हैं। भारतीय रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले तंदूरी चिकन से लेकर मटन बर्गर, पनीर मलाई कोफ्ता से लेकर सरसो दा साग तक के जायके स्थानीय लोगों के साथ-साथ वहां जाने वाले दूसरे देशों के लोगों को खूब लुभा रहे हैं और इन रेस्टोरेंट के संचालक आश्चस्त हैं कि आने वाले दिनों में भारत के मसालेदार व्यंजनों की मांग और बढ़ेगी। मास्को में जय हिंद, दरबार, खजुराहो, देवी कैफे, जगन्नाथ जैसे कुछ लोकप्रिय भारतीय रेस्टोरेंट हैं। भारतीय व्यंजन मास्को ही नहीं बल्कि रूस के अन्य शहरों में भी लोकप्रिय हैं। मसालेदार भारतीय खाना रूस में सभी आयु वर्ग के लोगों में पसंद किया जा रहा है। वहां के देवी कैफे रेस्टोरेंट के एक अधिकारी के मुताबिक वे लोग भारतीय और चीनी खाना परोसते हैं लेकिन लोगों द्वारा भारतीय खाना सबसे अधिक पसंद किया जाता है। रूसी लोग भारतीय व्यंजनों को पसंद करते हैं। वहां भारतीय रेस्टोरेंट में आने वाले 60-70 प्रतिशत लोग रूसी होते हैं। केवल 25-30 प्रतिशत विदेशी और भारतीय आते हैं।

अमेरिका में भारतीय भोजन

एक दशक पहले, यूएस के भारतीय रेस्तरां तैलीय, क्रीमी, गरिष्ठ व्यंजन जैसे पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, बटर नान, पनीर बटर मसाला और तंदूर में बनी अन्य चीजों से इतर ज्यादा कुछ प्रस्तुत नहीं करते थे। यह वास्तव में घर का बना मौलिक भोजन नहीं हैं। अब, भारतीय शेफ अपनी किस्म के पारखी होने का सम्मान हासिल कर रहे हैं, वे ज्यादा सजातीय भारतीय खाने को लोकप्रिय बना रहे हैं, जो घर पर बने भोजन के ज्यादा निकट है, और साथ-साथ वे इनके जायकों के विभिन्न

संस्करणों का प्रयोग भी कर रहे हैं। खाने का कोई भी शौकीन सुवीर सरन और स्लायड कार्डोज जैसे शेफों के नामों से परिचित होगा। पद्मा लक्ष्मी जैसी महिलाएं इसमें ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं, विकास खन्ना, जिन्होंने यूएस राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए खाना बनाया की प्रशंसा की जाती है। इनके अलावा कई फूड नेटवर्क शो में हिस्सा लेने वाले और अकसर जज बनने वाले मनीत चौहान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य श्रंखला ऑ बोन पेन के मेन्यू में सुधार करने वाली टीम के प्रमुख थॉमस जॉन और सचिन चोपड़ा, जिन्हें ए स क व | य र मैगजीन ने



संभावनापूर्ण घोषित किया, सराहे

जाते हैं। ये कुछ भारतीय शेफ हैं, जिन्होंने अमेरिकी पाक परिदृश्य में नए चलन स्थापित किए।

50 शीर्ष व्यंजनों में शुमार

भारतीय पकवानों और स्वाद की समृद्ध विरासत असीम है। यह सीमाओं को लांघ कर सुदूर, वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बटोर रही है। कुछ भारतीय पकवान बेहद लोकप्रिय हैं और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और अन्य मध्य-पूर्वी देशों में भी उपलब्ध हैं। द समाचार है। सीएनएन ट्रेवल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय व्यंजन विश्व के 50 शीर्ष व्यंजनों में शुमार किए जाते हैं। वास्तव में यह एक बहुत ही सुखद समाचार है। अंतर्राष्ट्रीय शेफ लोकप्रिय भारतीय व्यंजनों को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पकवान प्रभावित हुए हैं। भारतीय व्यंजनों को इस शीर्ष स्तर पर ले जाने का श्रेय उसकी सरलता, स्वादिष्टता एवं मितव्ययता को जाता है।

योग से कैंसर की रोकथाम...

एम्स के इंडियन कार्डिसल आफ मेडिकल रिसर्च विभाग की रिसर्च में ऐसे कैमिकल बनते हैं जिससे कैंसर बनाने वाली कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। इसके लिए इंडियन कार्डिसल ने 150 कैंसर मरीजों पर रिसर्च की और उन्हें लगातार तीन महीने तक प्रणायाम, सुददर्शन क्रिया और ध्यान करवाया गया। तीन महीने बाद ब्लड टेस्ट कराए गए और उसके जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। कैंसर मरीजों के शरीर में कार्टिसो लेवल कम पाया गया और डब्ल्यूएचओ स्तर के मुताबिक उन सभी की क्वालिटी आफ लाइफ में सुधार पाया गया।

तीसरी और चौथी स्टेज

अमूनन कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज को असहनीय दर्द होता है। ऐसे में मरीजों को माफिन की दवा दी जाती है ताकि उन्हें दर्द से निजात मिल सके। एम्स के कैंसर विभाग में प्रोफेसर सुषमा ऐसे ही मरीजों का इलाज करती हैं। उनका कहना है कि जब हमने रिसर्च की तो पाया कि योग करने वाले मरीजों में दर्द सहने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। एम्स के निदेशक डॉ. एम. सी मिश्रा इस रिसर्च से बेहद उत्साहित हैं और कहते हैं में

- वजन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपका फिट रहना जरूरी है। आप वजन बढ़ाना चाहते हैं इसका ये अर्थ नहीं कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होंगे।
- वजन बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, इसके लिए आप फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं।
- वजन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है आप हाई कैलोरी का खाना खाएं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप जंकफूड भारी मात्रा में खाने लगे।
- जंक फूड और फास्ट फूड की तुलना में स्वस्थ और अधिक कैलोरीयुक्त खाद्य-पदार्थों को प्राथमिकता दीजिए।
- अगर आप वजन हेन्दी रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सुबह का नाश्ता हेवी करना होगा। सुबह का नाश्ता करने आप दिनभर ऊर्जावान बने रहते हैं।

- वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन शेक भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे हड्डियां भी मजबूत होती है।
- चिकन, चावल, फिश, अंडा इत्यादि भी वजन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
- दूध या दूध से बनी चीजों में भी प्रोटीन पाया जाता है या फिर आप सोया मिल्क या पाउडर के सेवन से भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं।
- अंकुरित अनाज में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मौजूद होती है। आप अंकुरित चने, मॉठ इत्यादि के सेवन से अपना वजन बढ़ा सकते हैं।
- पनीर, मक्खन, घी, तेल, तैलीय भोजन सभी को खाने से मोटापा बढ़ाने में मदद मिलती हैं।



इन व्यंजनों ने बनाई अलग पहचान



मसाला-डोसा

मसाला-डोसा भारत के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों में से एक है और उन पकवानों में शुमार है जिन्हें एक वैश्विक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य चखना चाहिए।

आलू चाट

सड़क एवं गलियों से निकलकर भारत का प्रसिद्ध मजेदार स्नेक आलू चाट विदेशों में भी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। यह क्षुधावर्धक विभिन्न महाद्वीपों में व्यापक रूप से उपलब्ध है।



लिट्टी चोखा

जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। यह बिहारी स्वादिष्ट पकवान अब वैश्विक व्यंजन-सूचि में सम्मिलित हो चुका है। यह व्यंजन कम मात्रा में कैलोरी के साथ रेशे से भरपूर होने के कारण प्रसिद्ध है।

उपमा

उपमा, वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही बढ़िया और प्रसिद्ध पकवान है। सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड स्टीट फूड कांग्रेस से इसने अपनी पहचान बनाई। यह पकवान, विशेषतः उन लोगों के लिए है जो लजीज एवं स्वास्थ्यवर्धक खाने के शौकीन हैं।



कि एंड्राइड के अगले संस्करण का नाम भी 'मैंगो लस्सी' ही होगा ।

सबसे आसान तरीका

शरीर में कैंसर संक्रमित कोशिकाओं की रोकथाम का हमारे पास सबसे आसान तरीका समय से उपवास रखना है। इन कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं से ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती है और कुछ खास दिन खुद को भोजन से दूर रख कर आप शरीर में कैंसर संक्रमित उन कोशिकाओं की संख्याओं को कम कर सकते हैं। आप रोजाना नीम और हल्दी के पेस्ट से बनी गोलियां भी ले सकते हैं। यह कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए भले एक उपचार न हो, लेकिन यह शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को काबू में रखते हैं, जिससे वे शरीर के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाती हैं। जब शरीर में इनका स्तर बढ़ता है, तो यह कोशिकाओं में ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं और शरीर के वे हिस्से जहां ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता उनमें कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

आध्यात्मिक तरीके

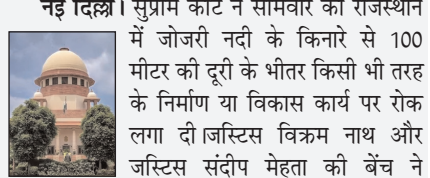
योग में कुछ खास किस्म के आध्यात्मिक तरीके भी हैं, जो शरीर प्रणाली को सुधारने और संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। कई ऐसे मरीजों को देखा गया है कि जो इन उपायों की बदौलत पूरी तरह ठीक हो गए हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जो योग के जरिए कीमोथेरेपी के बाद बड़ी ही तेजी से उससे उबर गए। उन मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर भी उन्हें देख कर दंग रह गए। यहां यह पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि योग की वजह से उनका कैंसर ठीक हो गया, लेकिन चिकित्सीय उपचार के साथ योग करने से कैंसर के मरीजों को फायदा जरूर मिला है।

- वजन बढ़ाने के लिए फुलक्रीम दूध में रात को चने भिगोकर सुबह खाने चाहिए। इस तरह के खाद्य पदार्थों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मौजूद होता है।
- फलियां, मेवा, बींस इत्यादि में भरपूर प्रोटीन मौजूद होता हैं। इनके सेवन से आप आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं।
- बहुत अधिक तैलीय पदार्थों के सेवन और तरल पदार्थों की कमी से भी वजन बढ़ता है।
- अधिक वसा इत्यादि का सेवन या फिर अधिक मात्रा में कैलोरी लेना लेकिन उस अनुसार व्यायाम ना करने से भी मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, फल, सूप इत्यादि के सेवन से भी आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। इन टिप्स से आप प्रोटीन की कमी को दूर कर अपना वजन बढ़ा सकते हैं।

सीजेपी का 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च का एलान

नई दिल्ली। काँकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर को युवा मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि सरकार जुलाई में हुए आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक जाएगा। संगठन ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई नीट के मारे गए पीड़ितों और कथित पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे और इसमें छात्रों और युवा संगठनों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पोस्ट में सीजेपी ने कहा, काँकरोच जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा भारत के युवाओं से 25 जुलाई को किए गए वादों को पूरा न करने की कड़ी निंदा करती है, खासकर उन वादों को जो छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने से जुड़े थे। पार्टी ने कहा, सरकार द्वारा अपने आश्वासनों को पूरा करने में लगातार देरी और डालमटोल करने के कारण, सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी ने शांतिपूर्ण तरीके से फिर से लामबंद होने का फैसला किया है।

जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान में जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह के निर्माण या विकास कार्य पर रोक लगा दी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी बेंच ने पर्यावरण को हुए गंभीर नुकसान और नदी की पारिस्थितिकी तंत्र के बड़े पैमाने पर विनाश का जिक्र किया। बेंच ने कहा, हमारी सोच यह है कि हाई फ्लाइंग लाइन और जरूरी इकोलाजिकल बफर जोन तय करने और उनकी सीमाएं निर्धारित करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान नदी के पारिस्थितिकी को ठीक से सुरक्षित रखने के लिए एक अंतरिम, निश्चित और मापने योग्य सुरक्षा क्षेत्र बनाना जरूरी है। इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि ऊपर बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार, नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी तरह की निर्माण या विकास गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

61000 मशीनों से जमा कराए 2904 करोड़ कैश



नई दिल्ली। ईडी को साइबर धोखाधड़ी की रकम को ध्वस्त करने में सफलता मिली है। एक घंटे के भीतर 400 से अधिक बैंक एकाउंट में धोखाधड़ी की रकम को ट्रांसफर करने वाले और अंततः उसे विदेश भेजने वाले इस नेटवर्क में आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त कई मनी चेंजर्स कंपनियां शामिल थीं। यही नहीं, जांच के दौरान इस नेटवर्क से शामिल कर्मांडीटी, ट्रेडिंग, ट्रेवल और फारेक्स में कई कंपनियों का पता चला, जो आपस में एक-दूसरे से जुड़ी थीं। 20 राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के 330 पीड़ितों की शिकायत और 163 एफआईआर में इस नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं। माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल हजारों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी की रकम को ठिकाना लगाने के लिए किया गया था। सिर्फ 330 शिकायतकर्ताओं और 163 एफआइआर में ही 417 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा तरुण तेजपाल की याचिका पर फैसला



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार तरुण तेजपाल की समर्पण करने से छूट की मांग करने वाली याचिका पर आदेश देगा।शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली। छह अगस्त को बांबे हाई कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई थी।जस्टिस आलोक अराधे की एकल पीठ की समझ गोवा सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तेजपाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने समर्पण करने से छूट के लिए कोई अलग याचिका नहीं दी थी।इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया है जिससे पता चले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत समर्पण कर दिया है। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू नहीं होते क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें समर्पण करने के लिए पहले ही चार हफ्ते का समय दिया था।

महिला आरक्षण और ‘वंदे मातरम’ को लेकर स्मृति की राहुल से अपील



नई दिल्ली। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से महिलाओं के आरक्षण और वंदे मातरम को लेकर अपील की है. स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून बनाया है, जिससे महिलाएं संसद की गरिमा बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकेंगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से इस महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने में सहयोग करने की अपील की है.स्मृति ने राहुल गांधी से इस कानून के जल्द लागू होने और महिलाओं को संसद में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलने का समर्थन करने की अपील की. स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें यह भी पता है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां की गई थी।

कांग्रेस में खींचतान: चन्नी ने दीपेंद्र को दी नसीहत

■ **पूर्व डिप्टी सीएम ने इन्हें सीएम चेहरा घोषित करने की मांग**

लुधियाना। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सतह पर आ गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर रार गहराती दिख रही है। लुधियाना में शक्ति प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सीधे दिल्ली हाईकमान को संदेश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी चुनाव में सीएम चेहरा घोषित करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है।

वहीं, दूसरी ओर 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को लेकर चन्नी के आक्रामक रुख

और केंद्रीय नेताओं पर टिप्पणी ने कांग्रेस हाईकमान को भारी धर्मसंकट में डाल दिया है।

लुधियाना में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व मंत्री भारत भूषण आरूप की मौजूदगी में रंधावा ने कहा कि पंजाब को मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चन्नी ने महज 111 दिनों के अपने कार्यकाल में जनहित के कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिन्हें प्रदेश की जनता आज भी याद करती है।

रंधावा ने कहा कि हमारे पास चन्नी के रूप में अनुसूचित जाति नेतृत्व, मेरे रूप में जट्ट सिख और आशू के रूप में ब्राह्मण/शहरी हिंदू चेहरा है। यह तिकड़ी 2027 के लिए



कांग्रेस की मजबूती का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने एलान किया कि वह फूड स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर पंजाब आने पर धान भंडारण और राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर सीधे पंजाब सरकार के अफसरों और मुख्यमंत्री से जवाब-तलबी करेंगे। एक तरफ जहां चन्नी को सीएम चेहरा बनाने की पैरवी हो रही है, वहीं चन्नी के बयानों ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। चन्नी ने 1984 के सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को सिखों का कातिल और गद्दार बताते हुए कहा कि दिल्ली में सिखों को जिंदा जलाने वाले को संरेआम गोली मार देनी चाहिए थी। इसके साथ ही सज्जन

कुमार को रोल मॉडल बताने वाले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए चन्नी ने उन्हें अपनी जुवान पर लागाम रखने और संभलकर बोलने की हिदायत दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1984 के दंगों जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बोलना और अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को निशाने पर लेना चन्नी के हाईकमान के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर हमेशा रक्षात्मक रुख अपनाती रही है, लेकिन चन्नी ने स्थानीय भावनाओं को भुगाने के लिए इसे आक्रामक मोड़ दे दिया है। लुधियाना में तीन बड़े नेताओं की एकजुटता के जरिए चन्नी खेमे ने यह साफ कर दिया है कि 2027 की बाजी स्थानीय और अनुभवी चेहरे को आगे रखकर ही जीती जा सकती है।

चिराग पासवान ने आरक्षण को बताया संवैधानिक अधिकार

पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है जिसे कोई भी अर्थार्थिटी खत्म नहीं कर सकती। उनका यह बयान जंतर-मंतर पर हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के जुवाब में आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित कोटा खत्म करने की मांग की थी। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि क्या आरक्षण कोई ऐसी चीज है जिसे सिर्फ इसलिए खत्म किया जा सकता है क्योंकि किसी ने ऐसा कह दिया ?

यह एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो किसी को बांट दी जाए; यह एक संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो आरक्षण व्यवस्था में सुधार या समीक्षा करना चाहते हैं, और कहा कि वे इसकी ज़रूरत को नहीं समझते। पासवान ने दलितों के साथ हो रहे भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस मंच पर खड़ेगे के साथ जो हुआ, उसे देखिए।

अयोध्या मछल दावत पर सियासत गरम!

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सोमवार को अयोध्या में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान आयोजित मछली की दावत को लेकर हुए विवाद पर भारतीय जनता पार्टी (ऋषट्ठक) की आलोचना की। खेड़ा ने आरोप लगाया कि पेपर लोक जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उछाला जा रहा है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने सवाल उठाया कि क्या कार्यक्रम में परोसे गए खाने पर चर्चा, अयोध्या में चंदे की कथित चोरी और पेपर लोक जैसे मुद्दों पर भारी पड़ सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मछली परोसने में कुछ भी गलत नहीं है और तर्क दिया कि खाद्य-पान की पसंद को

राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। खेड़ा ने बताया कि अजय राय शाकाहारी हैं और कहा कि अगर वह शाकाहारी न भी होते, तो भी मछली खाने में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें अयोध्या के एक बैंक्रेट हॉल में मछली तैयार की जा रही थी; इसी हॉल में राय के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया था।

स्थानीय धार्मिक हस्तियों ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई क्योंकि यह सावन के पवित्र महीने में आयोजित किया गया था। इसके बाद खाने-पीने की व्यवस्था एक राजनीतिक मुद्दा बन गई और बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की आलोचना की।

स्टेल प्रमुख समाचार

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास धोनी को पीछे छोड़ा

कोलंबो। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पंत ने विदेशी या न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट मैचों में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने चोट के बावजूद दूसरे दिन मैदान पर वापसी करते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की।

कोलंबो टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत ने विदेशी और न्यूट्रल वेन्यू पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पंत के नाम रिपोर्ट लिखे जाने तक 41.68 की औसत से 2,501 रन रजर्ज हो गए थे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 2,496 रन बनाए थे। इस सूची में फारुख इंजीनियर 1,209 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। सैयद किरमानी ने 1,109 रन बनाए हैं, जबकि किरण मोरे 901 रनों के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के दौरान चोट लग गई थी। भारतीय पारी के तीसरे सत्र में लाहिरू कुमारा की एक शॉर्ट गेंद पंत के बाएं हाथ पर लगी। पंत ने गेंद को स्क्वायर के पीछे मिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वह गेंद को पुल करके बैठे और गेंद सीधे उनके बाएं हाथ पर जा लगी। चोट लगने के बाद पंत दर्द में नजर आए और भारतीय टीम के फिजियो ने तुरंत मैदान पर पहुंचकर उनका इलाज किया।

चोट के बाद पंत के हाथ पर पहले आइस पैक लगाया गया और फिर उसे बांधा गया। हालांकि, वह लगातार असहज दिखाई दे रहे थे। आखिरकार पंत 15 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने के बाद भारतीय पारी के 58वें ओवर में फिजियो के साथ मैदान से बाहर चले गए और रिटायर्ड हट हो गए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 170 अंक टूटकर बंद, बैंक शेयर लुढ़के

नईदिल्ली। भारतीय बाजारों में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन कमजोरी दर्ज की गई। सोमवार (24 अगस्त) को बेंचमार्क इंडेक्स 2 सेशन बाद लाल निशान में बंद हुए, जबकि सुबह बढ़त के साथ शुरुआत हुई थी। एनएसई निफ्टी 50 करीब 33 अंक गिरकर 24219 पर बंद हुआ, जो कारोबार के दौरान 24,313 तक उछला। बीएसई सेंसेक्स भी दिन के हाई 77,789 से टूटकर 77,369 पर बंद हुआ, जो शुक्रवार के बंद स्तर से 171 अंक नीचे है। घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा कमजोरी बैंकों के शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.93 फीसदी गिरा। जबकि मेटल सेक्टर में चमक देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.6 फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 में शामिल 50 में से 26 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट एस्सीआई लाइफ, अडानी पोर्ट्स के शेयरों में दर्ज की गई।

खाद्य तेल की कीमतों में आएगा अभी और उबाल

नईदिल्ली। आगामी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने और वैश्विक बाजारों में तेजी के कारण आयातित खाद्य तेलों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। पिछले एक महीने में खाद्य तेलों के दाम करीब 15 फीसदी बढ़ चुके हैं। त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए तेल रिफाइनरी कंपनियां आयात बढ़ाने में लगी हुई है। उद्योग जगत का अनुमान है कि चालू महीने में सोयाबीन का आयात 6.20 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा मासिक औसत से करीब 46 प्रतिशत अधिक है। हालांकि आयात में आ रही रुकावट स्पलाई बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। खाद्य तेल की कीमतों में भी त्योहारी खुमार चढ़ने लगी है। अगस्त महीने में खाद्य तेलों के दाम करीब 15 फीसदी महंगे हो गए। जो आगामी त्योहारी सीजन में और भी महंगे हो सकते हैं।

टाटा ग्रुप का होटल कारोबार होगा और मजबूत

नईदिल्ली। टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) ने सोमवार को ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड के अपने साथ विलय की घोषणा की। यह विलय पूरी तरह शेयरों के लेनदेन के जरिये किया जाएगा। दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विलय के अंतर्गत ओरिएंटल होटल्स के प्रत्येक 117 शेयरों के बदले शेयरधारकों को आईएचसीएल के 25 शेयर मिलेंगे। कंपनी का लक्ष्य इस सौदे को वित्त वर्ष 2028 की दूसरी छमाही में पूरा करने का है। इंडियन होटल्स के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत छतवाल ने कहा कि यह विलय कंपनी की ‘Accelerate 2030’ रणनीति के अनुरूप है। इसका मकसद शेयरधारकों के लिए बेल्यू तैयार करना, समूह के होल्डिंग्स ढांचे को सरल बनाना और ओरिएंटल होटल्स के पोर्टफोलियो की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना है।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले फिसला कूड ऑयल

नई दिल्ली। ईरान पर अमेरिकी की नई और कड़ी आर्थिक कार्रवाई के ऐलान से पहले सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने पिछले सप्ताह की तेजी के बाद मुनाफावसूली की और अब बाजार की नजर अमेरिकी प्रतिबंधों के नए पैकेज पर है। सोमवार के शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड करीब 1.3% गिरकर 93.16 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। वहीं अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब 1.6% फिसलकर 85.70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इससे पहले दोनों बेंचमार्क पिछले सप्ताह 5% से ज्यादा चढ़े थे। बाजार में गिरावट की एक वजह निवेशकों की मुनाफावसूली है, जबकि दूसरी बड़ी वजह अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों को लेकर बनी अनिश्चितता है।

खाद्य तेलों का आयात बढ़ा, आत्मनिर्भरता की राह में तकनीक नहीं नीतियां बन रहीं बाधा

सुरिंदर सूद

वनस्पति तेल उद्योग के आकलन के अनुसार चालू तेल वर्ष (नवंबर से अक्टूबर) में करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये तक के खाद्य तेलों का आयात हो सकता है। तेल आयात पर इतना खर्च कभी नहीं हुआ और पिछले साल के 1.61 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड से भी यह करीब 9 प्रतिशत ज्यादा रहेगा। आयात पर खर्च बढ़ने का सबसे बड़ा कारण देश में खाद्य तेलों की बढ़ती मांग और उत्पादन के बीच बढ़ता अंतर है। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने, इंडोनेशिया में जैव ईंधन के कारण पाम ऑयल की उपलब्धता घटने और रुपया गिरने से भी आयात का खर्च बढ़ा है। खाद्य तेलों के आयात में लगातार वृद्धि ने निकट भविष्य में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

देश में तिलहन का उत्पादन लगातार

बढ़ने के बाद भी आयात में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले कई दशकों में इस समस्या को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। आज भी देश में खाद्य तेल की आधी से अधिक जरूरत आयात के जरिये पूरी होती है।

खाद्य तेल जैसी आम जरूरत की वस्तु के लिए आयात पर इतना निर्भर रहना सही नहीं है। स्थिति चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि हम पाम ऑयल और उससे जुड़े उत्पादों का सबसे ज्यादा आयात करते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से खरीदा जाता है। इन देशों से आपूर्ति में किसी भी कारण से रुकावट आई तो खाद्य तेल के सबसे बड़े आयातक भारत के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। वनस्पति तेल ऐसी वस्तु भी नहीं है, जिसका पर्याप्त उत्पादन

देश में नहीं किया जा सकता।

भारतीय कृषि वैज्ञानिक देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी तकनीक पहले ही तैयार कर चुके हैं। अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए तिलहन फसलों की 1,000 से अधिक उन्नत किस्में और संकर बीज विकसित किए जा चुके हैं। तिलहन फसलों की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 1950 के दशक में केवल 4.8 क्विंटल थी, जो इन किस्मों की वजह से बढ़कर अब करीब 14 क्विंटल हो गई है। फिर भी औसत राष्ट्रीय उपज और नई उन्नत किस्मों की संभावित उपज के बीच काफी अंतर है। नई किस्मों से प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल तक फसल उगाई जा सकती है। यह खाई पूरी तरह या काफी हद तक पाट दी गई तो खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा



सकती है।

इसके लिए कृषि मूल्य निर्धारण नीतियां भी बदलनी होंगी। तिलहन की खेती किसानों के लिए दूसरी फसलों जितनी लाभदायक बनेगी तभी वे इसका रकबा बढ़ाने, उन्नत बीज और कृषि के नए तरीके अपनाने तथा सिंचाई, उर्वरक और पौधों को संरक्षण देने वाले रसायन जैसे पैदावार बढ़ाने वाली सुविधाओं में निवेश करेंगे। मूल्य निर्धारण और सरकारी खरीद की मौजूदा नीतियों से किसानों को अच्छी व उपजाऊ भूमि पर ज्यादा मुनाफा देने वाली खाद्य और व्यावसायिक फसलें उगाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए तिलहन की खेती के लिए कम उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा से रहित जमीन रह जाती है। वास्तव में तिलहन की खेती का लगभग 75 प्रतिशत रकबा अब भी सिंचाई की सुविधा से वंचित

है।

सौभाग्य से वनस्पति तेलों में जैसी विविधता भारत में है वैसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। मृंगफली, सरसों-राई और सोयाबीन सहित नौ प्रमुख तिलहन फसलों के अलावा नारियल और ऑयल पाम जैसी बारहमासी फसलें भी हैं। साथ ही मुख्य रूप से आसिवासी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली कुछ फसलें भी हैं, जिनमें तिलहन के पेड़ होते हैं। बिनीले यानी कॉल्टनसिड और चवला की भूसी जैसे अपारंपिक स्रोतों से भी तेल का उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है, जो भारत में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। इन्हें से कुछ तेल तो पाम ऑयल से ज्यादा सेहतमंद होते हैं।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए संगठित प्रयास 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुए, जब 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई।

Chhattisgarh
full of surprises
Chhattisgarh Tourism Board

जन-जन की आस्था का सेतु बनी 'रामलला दर्शन योजना'

श्रद्धा से सम्मान और आस्था से आत्मविश्वास तक की ऐतिहासिक यात्रा

प्रभु श्रीराम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और प्रदेशवासियों को उनके दर्शन कराना शासन के लिए सौभाग्य का विषय है। सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही जनसेवा की वास्तविक संतुष्टि है, और सरकार इसी भावना के साथ कार्य कर रही है।

- श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

भारतीय संस्कृति में तीर्थाटन केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक चेतना और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन करना प्रत्येक भारतीय के जीवन का सर्वोच्च संकल्प होता है। दशकों तक आर्थिक और व्यवस्थागत बाधाओं के कारण कई श्रद्धालु इस सौभाग्य से वंचित रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की 'रामलला दर्शन योजना' इन सपनों को हकीकत में बदल रही है।

आंकड़ों में श्रद्धा की गूँज

यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों के प्रति शासन की संवेदनशीलता का प्रतिबिंब है। विशेष ट्रेनों के माध्यम से करीब 47 हजार 600 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम की पुण्य यात्रा कर चुके हैं। जब कोई बुजुर्ग श्रद्धालु वर्षों के इंतजार के बाद अपने आराध्य के सम्मुख भावविभोर होता है, तब इस योजना का वास्तविक उद्देश्य सफल होता है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा इस यात्रा को अत्यंत गरिमापूर्ण बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित परिवहन और गुणवत्तापूर्ण भोजन, स्वच्छ आवास और निरंतर स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी प्राथमिकता है, कि प्रत्येक यात्री सम्मान और आत्मीयता के साथ इस आध्यात्मिक अनुभव को अपने हृदय में संजोकर लौटे।

सांस्कृतिक और सामाजिक समावेश

यह गरीब, जरूरतमंद, बुजुर्ग और सामान्य नागरिकों के सपनों को साकार करने का एक संवेदनशील प्रयास है। यह योजना समाज के हर वर्ग, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समान रूप से जोड़ रही है। प्रभु श्रीराम के आदर्शों (मर्यादा, करुणा और न्याय) को जीवन का हिस्सा बनाना ही हमारा विनम्र प्रयास है। यह पहल न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक गौरव और आत्मविश्वास का भी संचार कर रही है।

सरल और पारदर्शी चयन प्रक्रिया

शासन की सफलता 'अंतिम व्यक्ति' तक लाभ पहुँचाने में है। रामलला दर्शन योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक नागरिक जिला कलेक्टर कार्यालय, जनपद पंचायत, या नगर निगम से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाता है। यात्रा से पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

भविष्य का विजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार "सबका साथ, सबका विकास" और "जनहित सर्वोपरि" के मंत्र पर कार्य कर रही है। हमारा संकल्प है, कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और अधिक व्यापक हो। छत्तीसगढ़ सरकार जनआस्था, सांस्कृतिक गौरव और लोककल्याण के इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह केवल अयोध्या तक की यात्रा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा से सम्मान, आस्था से आत्मविश्वास और जनकल्याण से सांस्कृतिक उत्थान की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ का एक दृढ़ कदम है। मुझे विश्वास है, कि यह योजना आने वाले वर्षों में जनसेवा और सांस्कृतिक समन्वय के एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित होगी।



रायगढ़: मुख्यमंत्री की पहल, रामलला के दर्शन के सपनों को मिले नए पंख



छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत पिछले दिनों रायगढ़ जिले के 112 श्रद्धालुओं का 16वां जल्था भक्ति और उत्साह के साथ अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। वर्षों से प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि के दर्शन की अभिलाषा संजोए बुजुर्गों और ग्रामीणों के लिए यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं था। श्रद्धालुओं को रायगढ़ जिला पंचायत परिसर से बसों के माध्यम से बिलासपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहाँ से वे विशेष ट्रेन द्वारा अयोध्या प्रस्थान करेंगे। इस जल्थे में 84 ग्रामीण और 28 शहरी क्षेत्रों के श्रद्धालु शामिल हैं। रवानगी के दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के जयघोष से गुंजायमान रहा, जहाँ परियत्रों ने भावुक मन से अपने प्रियजनों को विदा किया। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की इस योजना ने उन लोगों का सपना सच कर दिया है, जो आर्थिक बाधाओं के कारण अयोध्या जाने में असमर्थ थे। महिला श्रद्धालु ने कहा कि बचपन से रामायण में राम जन्मभूमि के बारे में सुना था, पर साक्षात् दर्शन का सौभाग्य आज मिल रहा है। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई वृद्ध यात्रियों ने इसे प्रभु का साक्षात् बुलावा बताते हुए शासन की इस पहल को सराहनीय बताया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी यात्रियों का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। यात्रा के दौरान निःशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशेष टीम भी जल्थे के साथ भेजी गई है। जिला प्रशासन ने यात्रियों को भावभीनी विदाई देते हुए कहा कि शासन का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित और सम्मानजनक तीर्थ यात्रा कराना है।

बिलासपुर: डबल सौभाग्य अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ के भी दर्शन



छत्तीसगढ़ की धरा पर पिछले दिनों आस्था और सुशासन का एक अनुपम संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना के तहत रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालु एक विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु रवाना हुए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर विदाई का दृश्य ऐसा था, मानो पूरा शहर भक्ति के रस में डूब गया हो। रामलला दर्शन योजना आज छत्तीसगढ़ में केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-जन की आस्था का सेतु बन चुकी है। यह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्रद्धालुओं की रवानगी को एक उत्सव का रूप दिया गया। स्टेशन परिसर में पारंपरिक लोकनृत्य की थाप और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के बीच यात्रियों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। यात्रियों के आत्मीय स्वागत ने इस धार्मिक यात्रा को सामाजिक एकता और गौरव का प्रतीक बना दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और श्रद्धालुओं को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं। यह योजना विशेष रूप से उन वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनके लिए अयोध्या की यात्रा एक अपूरा सपना थी।

रायपुर: मानो पूरा शहर भक्ति के रस में डूब गया हो



अयोध्या धाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हो रही विशेष ट्रेन को राजधानी रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूरा स्टेशन जय श्रीराम और रामलला हम आएंगे के नारों से सराबोर रहा। इस यात्रा की विशेष बात यह है कि श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के साथ-साथ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। यात्रियों ने इसे अपना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताते हुए कहा कि एक ही यात्रा में दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग और धर्मों के दर्शन मिलना सुखद है। यात्रा पर रवाना हो रहे बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यात्रियों की आंखें भावुक थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अयोध्या जाने का सपना केवल एक कल्पना थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरी गरिमा और निःशुल्क व्यवस्था के साथ साकार कर दिया है।



योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता



यात्रा, भोजन, आवास, चिकित्सा और सुरक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करती है।



आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच हो।



जिला कलेक्टर कार्यालय, जनपद पंचायत या नगर निगम से आवेदन किया जा सकता है।



आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य।



बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा।

रामलला दर्शन योजना : छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील पहल, जो श्रद्धा को सम्मान और आस्था को आत्मविश्वास में बदल रही है।